दैनिक
रेवांचल टाइम्स
निष्पक्ष, निर्भीक एवं सत्य का प्रवर्तक

Revanchal Times
7509202320
@revanchal_times
revanchaljabalpur@gmail.com
revanchaltimes_

वर्ष - 10 ■ अंक - 193 ■ मंडला, सोमवार 28 सितम्बर 2026 ■ पृष्ठ-8 ■ मूल्य-1 रूपये ■ विक्रम संवत् 2083 ■ www.revanchaltimes.com RNI. Reg. No MPHIN/2016/69877

सुविचार

अहसास के साथ आप जो कुछ भी यकीन करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है।

ब्रायन ट्रेसी

प्रवेश वर्मा ने युवक को मारा थप्पड़, सड़क की गुणवत्ता पर विवाद के बाद गरमाई सियासत

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के तिलक नगर में रविवार को सड़क निरीक्षण के दौरान दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक जरनैल सिंह के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान सामने आए एक वीडियो में प्रवेश वर्मा एक युवक का मोबाइल नीचे करते और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद आप ने मंत्री पर हमला बोलते हुए कार्रवाई की मांग की है।



घटना उस समय हुई जब प्रवेश वर्मा इलाके में सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। आप विधायक जरनैल सिंह ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सड़क का एक हिस्सा उखाड़कर मंत्री को दिखाया। दोनों के बीच सड़क निर्माण को लेकर बहस भी हुई। इसके बाद प्रवेश वर्मा वहां से जाने लगे। इसी दौरान एक युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा था, जिसे मंत्री ने पहले हाथ से नीचे किया और फिर थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों ने युवक को मंत्री से दूर किया। थप्पड़ का वीडियो सामने आने के बाद आप नेताओं ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि सड़क निर्माण में कथित गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछे जाने पर यह घटना हुई। आप नेताओं ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं हुई है। घटना में थप्पड़ खाने वाले युवक की पहचान साहिब सिंह के रूप में बताई गई है। उसने कहा कि वह स्थानीय विधायक के सोशल मीडिया से जुड़े काम देखता है और पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क की स्थिति देखने के लिए वहां पहुंचा था। उसके मुताबिक, उसने मंत्री को सड़क की उखड़ती सतह दिखाई, जिसके बाद कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई। युवक ने अपने साथियों की ओर से जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं, प्रवेश वर्मा ने घटना पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आप की ओर से साझा किया जा रहा वीडियो पूरी घटना का संदर्भ नहीं दिखाता। उनका दावा है कि आप विधायक जरनैल सिंह से जुड़े लोगों ने उनके परिवार के बारे में गाली-गलौज की थी, जिसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वर्मा ने कहा कि विकासपुरी रिंग रोड क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम चल रहा है और वह काम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्रवेश वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि जरनैल सिंह पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों पर ठेकेदार से मिलवाने और कमीशन की व्यवस्था कराने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में विभाग के एक इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत की है और प्राथमिकी दर्ज किए जाने की कार्रवाई चल रही है। इन आरोपों पर आप की ओर से अलग पक्ष रखा गया है। वीडियो में प्रवेश वर्मा और जरनैल सिंह के बीच सड़क की गुणवत्ता को लेकर तीखी बहस भी दिखाई देती है। जरनैल सिंह सड़क का उखड़ा हुआ हिस्सा दिखाते हुए निर्माण पर सवाल उठाते हैं, जबकि प्रवेश वर्मा जवाब में कहते हैं कि गलत बात नहीं कही जानी चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक बहस होती है और प्रवेश वर्मा वहां से आगे बढ़ जाते हैं। घटना के बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया है। आप नेताओं ने मंत्री के आचरण पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रवेश वर्मा ने पूरे घटनाक्रम को कथित गाली-गलौज और विवाद की पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए अपना पक्ष रखा है। फिलहाल सामने आए वीडियो, दोनों पक्षों के आरोपों और शिकायतों के आधार पर विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है।



सीएम बोले- राहुल गांधी से कुनबा नहीं संभल रहा

भोपाल। मध्यप्रदेश में रक्षकको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से अपना कुनबा नहीं संभल रहा है। वे अपने साथियों की गिरेबान में हाथ डालते-डालते उनकी गर्दन दबाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपना गठबंधन और संगठन संभालना चाहिए। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रक्षकको लेकर कांग्रेस पर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर बार-बार आरोप लगाने और जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।

मोहन यादव बोले- कांग्रेस अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही- मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजनीति में एक तरफ ठऊअ है और दूसरी तरफ वढअ। उन्होंने कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ उसके संबंधों पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, "अखिलेश रायबरेली जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि मैं सैफई में भी आ सकता हूं।" मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस का अपना कुनबा ही नहीं संभल रहा। वह अपने साथ खड़े लोगों की गिरेबान में हाथ डालते-डालते उनकी गर्दन दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर दूसरे राजनीतिक दलों में गए नेताओं का भी जिक्र किया।

रक्षकके आरोपों पर बोले- नाच न जाने, आंगन टेढ़ा- रक्षकको लेकर कांग्रेस के आरोपों पर मोहन यादव ने कहा कि "नाच न जाने, आंगन टेढ़ा" वाली स्थिति कांग्रेस की है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे युवा देश है। ऐसे में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसद की मर्यादा का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के पुराने राजनीतिक बयानों का जिक्र करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और 'चौकीदार चोर' जैसे मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए पहले भी माफी मांगनी पड़ी है। **राहुल गांधी से माफी की मांग-** मोहन यादव ने कहा कि चुनाव आयोग रक्षकको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। फॉर्म-6 के डिक्लेरेशन और रक्षकके निर्णय को लेकर भी आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के आधिकारिक निर्णय पर बार-बार सवाल उठाना उचित नहीं है।

खंडेलवाल बोले- कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस रक्षकको लेकर चुनाव आयोग पर बार-बार आरोप लगाकर जनता में भ्रम और अविश्वास पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को तीनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से रक्षकके निर्णय को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। खंडेलवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आंतरिक विचार-विमर्श सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे आधार बनाकर राजनीतिक आरोप लगाना गलत है।

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची पर घमासान

एमपी में मतदाता सूचियों में 27.4 लाख का अंतर, निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस कराएगी घर-घर सत्यापन



भोपाल। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कर सूची तैयार की। इसमें मतदाताओं की संख्या 5,39,81,065 रही, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर से जो सूची तैयार कराई, उसमें मतदाताओं की संख्या 5,67,21,353 रही। इस प्रकार दोनों सूचियों में 27,40,288 मतदाताओं का अंतर है। चूंकि, यह बड़ी संख्या है इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि वह मतदाता सूची का सत्यापन कराएगी। इसके लिए 71,930 बूथ लेवल एजेंटों को घर-घर भेजा जाएगा।

मतदाता सूची में नाम हटाने और जोड़ने पर कांग्रेस की आपत्तियां- कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर लगातार आपत्ति उठाती रही है। पार्टी का आरोप है कि जो नाम काटे गए, उनमें से कई पात्र थे। जबकि, एक ही मकान के पते पर कई मतदाताओं के नाम जोड़े गए। **बीएलए करेंगे घर-घर सत्यापन, गड़बड़ी मिलने पर देंगे ज्ञापन-** प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि जिन सूचियों के आधार पर चुनाव होने हैं, उन्हें लेकर कई सवाल हैं इसलिए एक-एक मतदाता का सत्यापन कराया जाएगा। इसमें बूथ लेवल एजेंट घर-घर जाएंगे और देखेंगे कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं वे वास्तव में हैं भी या नहीं। इसके साथ ही जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं, वे वहां रहते हैं या नहीं। यह भी पढ़ें- एमपी मंत्रालय में लेटलतीफी पर कसेगी नकेल, अक्टूबर से लागू होगी 'फेस रिकग्निशन' अटेंडेंस, जिलों में भी लागू करने का प्लान यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर सूची में सुधार के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजी जाएगी।

रविवार होने के बावजूद सरकारी बैंक खुले:कैश और चेक जमा करने पहुंचे लोग, आज से 3 दिन बंद रहेंगे

दिल्ली। आज रविवार को छुट्टी होने के बावजूद सरकारी बैंक खुले। कल से बुधवार तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी की मांग को लेकर अगले 3 दिन हड़ताल करेंगे। रविवार को आम लोगों के लिए बैंक खुलने का मौका 10 साल बाद आया था। इससे पहले, 2016 में नोटबंदी के बाद 14 नवंबर को रविवार के दिन बैंक खुले थे। तब पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने, जमा करने और कैश निकालने के लिए लोग बैंकों में लाइन में लगे थे। भीड़ संभालने के लिए सरकार ने रविवार को भी बैंक खोलने का फैसला लिया था। **ATM से कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं-** बैंक हड़ताल के दौरान रइकऔर ढठइ सहित सभी सरकारी बैंकों के अळट से मंथली फ्री लिमिट खत्म होने के बाद भी कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। पइकके नियमों के मुताबिक, अभी अपने बैंक के अळट से हर महीने 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के अळट से दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार और छोटे शहरों में 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट है। अगर आप एक महीने में लिमिट से ज्यादा बार अळट से कैश निकालते हैं, तो हर बार 23 + GST चार्ज कटता है। इसके अलावा जब आप अळट का इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक भी एक-दूसरे को फीस देते हैं- कैश निकालने पर 19 रुपए और बैलेंस चेक करने पर 7 रुपए।

हड़ताल पर अड़ीं यूनियन, 90% कर्मचारी शामिल होंगे- वित्तीय सेवा विभाग, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक प्रबंधन की हड़ताल टालने अपील को यूनियनों ने ठुकरा दिया है। हड़ताल में देश की 7 बड़ी बैंक यूनियनें शामिल होंगी, जिनसे लगभग 90% से ज्यादा बैंक कर्मचारी जुड़े हैं। इनमें AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF और वइइउ शामिल हैं। यूनियंस का कहना है कि जब तक सरकार हफ्ते में 5-डे वर्किंग लागू करने की कोई पक्की तारीख तय नहीं कर देती, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। **बैंकों में 5-डे वर्किंग पर सरकार का इनकार-** बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से ठीक पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, सरकार ने कभी भी बैंकों के लिए 5-डे वर्किंग का वादा नहीं किया था और सैलरी रिवीजन की बातचीत के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। वित्त मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि यह मांग कर्मचारी यूनियनों की तरफ से एकतरफा उठाई थी और दोनों पक्षों के बीच इस पर कोई सहमति नहीं बनी थी। हफ्ते में 5 दिन काम के अलावा बोनस (ढछछ) के नियमों को लेकर भी विवाद चल रहा है। सरकार ने बड़े अधिकारियों जैसे स्केल-4 और उससे ऊपर के अफसरों के लिए बोनस का एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत अच्छा काम करने वाले अफसरों को 365 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है।

न डॉक्टर बन पाया, न खिलाड़ी

इंदौर/देवास। मेरी मां चाहती थीं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं सॉफ्टबॉल में करियर बनाना चाहता था। कोरोना में मां की मौत के बाद उनकी इच्छा पूरी करने का फैसला लिया, लेकिन ठएएळ ने मेरा सपना तोड़ दिया। जब 23 साल का वरुण सोलंकी यह बात कहता है, तो उसकी आवाज में बेबसी और सिस्टम के लिए तल्खी साफ झलकती है। देवास का रहने वाला वरुण इंटरनेशनल सॉफ्टबॉल खिलाड़ी है। 2022 में उसने जापान में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आज वह ऐसे मोड़ पर है, जहां उसका खेल करियर भी छूट गया और डॉक्टर बनने का सपना भी अधूरा रह गया। वरुण ने 10 साल की उम्र में सॉफ्टबॉल खेलना शुरू किया था। उसने बताया, "मेरे पापा कंपाउंडर रहे हैं और मां सरकारी टीचर थीं। मां चाहती थीं कि मैं डॉक्टर बनूं।



इंदौर भेजने पिता ने रुपए उधार लिए, बेटा अफसर बना:किसान का बेटा पवन MPPSC में सातवीं रैंक लाकर मध्यप्रदेश में सहायक प्राध्यापक बना

भिंड। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और उसे इंदौर पढ़ने भेजा। यह कहना है भिंड निवासी पवन कुमार के किसान पिता सत्येंद्र कुमार तिवारी का। पवन ने टढढरउ सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र परीक्षा-2024 में प्रदेश में सातवीं रैंक हासिल की है। एहर वर्ग में उनकी पहली रैंक रही। उनका चयन मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर हुआ है। भिंड की लहार तहसील के रावतपुरा खुर्द गांव के रहने वाले पवन किसान परिवार से हैं। उन्होंने इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। इसके बाद टढढरउ समेत दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रयास किए। कुछ में असफलता मिली तो कुछ में चयन हुआ, लेकिन सहायक प्राध्यापक बनने के लक्ष्य के लिए तैयारी जारी रखी।

पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे, परिणाम अटक गया- पवन ने लहार के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद शासकीय महाविद्यालय, लहार से बीएससी किया। आगे की पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। ग्वालियर के डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए किया। वर्ष 2019 में उन्होंने टढढरउ राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। इसके बाद लगातार अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास करते रहे। वर्ष 2020 में पवन ने पहली बार टढढरउ राज्य सेवा परीक्षा दी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचे। 87-13 फॉर्मूले से जुड़े मामले के कारण परिणाम अटक गया और उस प्रयास में चयन नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने तैयारी जारी रखी और अगले प्रयासों में भी टढढरउ की परीक्षा दी। **लगातार दो प्रयासों में मुख्य परीक्षा नहीं निकली-** वर्ष 2021 में पवन टढढरउ की मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सके। वर्ष 2022 में भी मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली। इसी दौरान उन्होंने वऋछ-ठएळ क्वालिफाई किया। इसके बाद ररउ के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उनका चयन हुआ और उन्हें पहली सरकारी नौकरी मिली। **चेन्नई में नौकरी के बाद रात तक पढ़ाई की-** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में चयन के बाद पवन की पोस्टिंग चेन्नई में हुई। उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक थी। नौकरी से लौटने के बाद वह खुद खाना बनाते और फिर पढ़ाई करते थे। नौकरी और तैयारी साथ चलाने के दौरान कई बार रात 3-4 बजे तक पढ़ाई की। सुबह फिर नौकरी पर जाना होता था। इसके बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी।

सहायक प्राध्यापक परीक्षा में इंटरव्यू के बाद वेटिंग- पवन ने टढढरउ की सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र परीक्षा में भी प्रयास किया। लिखित परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन सूची में नाम वेटिंग में रहा। इस प्रयास में चयन नहीं होने के बाद भी उन्होंने तैयारी जारी रखी और सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान पवन का टढएइ के माध्यम से गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में मेडिकल सोशल वर्कर के पद पर चयन हुआ। इसके अलावा दिल्ली सरकार में वेलफेयर ऑफिसर के पद पर भी उनका चयन हुआ। इन चयन के बाद भी उन्होंने सहायक प्राध्यापक बनने का लक्ष्य नहीं छोड़ा। उन्होंने टढढरउ सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र परीक्षा-2024 के लिए आवेदन किया। पवन ने सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा दी और चयन प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंचे। इंटरव्यू के बाद जारी परिणाम में उन्होंने प्रदेश में सातवीं रैंक हासिल की।

जर्मनी-जापान का विरोध किया, सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर, भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा

रूस का UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन

मास्को। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। हम ब्राजील और भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। लावरोव ने सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों की अतिरिक्त सीटों का विरोध किया। उन्होंने खासतौर पर जर्मनी और जापान का नाम लेते हुए उन पर 'सैन्यवाद और बदले की भावना की ओर बढ़ने का आरोप लगाया। लावरोव ने साथ ही कहा कि वठरउ में सुधार के दौरान मौजूदा स्थायी सदस्यों के अधिकारों और शक्तियों में कमी नहीं होनी चाहिए।



भारत वठरउ में छठी परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार- दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। वठरउ में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। पिछले एक दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। यह चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस आर्थिक ताकत को वठरउ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करता। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो परमाणु निरस्त्रीकरण प्रोग्राम में वह अहम भूमिका निभा सकता है। **भारत की स्थायी सदस्यता की मांग 1990 से जारी-** भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग 1990 के दशक से उठती रही है। 2008 से वठ में सुरक्षा परिषद सुधार पर औपचारिक बातचीत शुरू हुई। 2010 में भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ G4 समूह बनाकर स्थायी सीट की मांग आगे बढ़ाई। 2026 में भी सुधार को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन सदस्य देशों के बीच वठरउ के नए ढांचे पर सहमति नहीं बनी है।

परिषद के सदस्य 15, वीटो राइट सिर्फ 5 को

सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य- अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। इन सबको वीटो पावर हासिल है। इसके अलावा 10 गैर-स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बढ़ाने के लिए वठ चार्टर में बदलाव करना होगा। इसके लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत और दो-तिहाई सदस्य देशों की औपचारिक मंजूरी जरूरी है। इसमें सभी पांच मौजूदा स्थायी सदस्यों की मंजूरी भी आवश्यक है।

स्थायी सदस्यता को लेकर 4 मुश्किलें

1. चीन का विरोधी रुख- भारत की स्थायी सदस्यता पर चीन का रुख सबसे महत्वपूर्ण अड़चनों में से एक माना जाता है। चीन के भारत के साथ क्षेत्रीय व रणनीतिक मतभेद भी हैं। उसने स्थायी सदस्यता को लेकर भारत का कभी भी समर्थन नहीं किया है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील स्थायी सीटों के विस्तार का समर्थन करते हैं। लेकिन वल्ल३ल्लें ाङ्म१ उङ्मल्लश्रील्ल२४२ (वाउ) जैसे समूह का एक प्रस्ताव है कि वठरउ में नए स्थायी सदस्यों के बजाय गैर-स्थायी सीटें बढ़ाई जाएं। **3. अफ्रीकी देशों की सीटों पर सहमति न बनना-** अफ्रीकी देशों की मांग भी वठरउ सुधार का बड़ा हिस्सा है। कितनी सीटें होंगी और उनका स्वरूप क्या होगा, इस पर भी बातचीत जारी है। अभी तक सर्वसम्मति नहीं बन सकी है। नए स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिलेगी या नहीं, यह सबसे जटिल मुद्दों में से एक है। मौजूदा पांच स्थायी सदस्य अपने अधिकारों को बनाए रखने पर जोर देते हैं। ऋ स्थायी सदस्यता के वास्तविक अधिकारों की बात करता है, जिसमें वीटो राइट्स भी शामिल हैं।

मां रेवा पब्लिकेशन एंड प्रिंटर्स
जबलपुर शहर में सबसे कम दामों में
समाचार पत्र के A to Z कार्य का एकमात्र स्थान
प्रिंटिंग
जॉब वर्क
न्यूज पेपर
पीडीएफ
संपर्क करें
7415685293
9589490996
9340553112
68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड, मुस्कान प्लाजा के पीछे, एम आर 4 रोड, उखरी, जबलपुर (मप्र)

राष्ट्रीय बैंक हड़ताल के समर्थन में बैंक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन

लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग, 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (**UFBU**) के आह्वान पर प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के समर्थन में जबलपुर में विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन में शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल उद्यान, विजय नगर स्थित एसबीआई चौक एवं आईसीआईसीआई बैंक के सामने बैंककर्मियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन और नारेबाजी की।प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) द्वारा प्रस्तावित परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) में भेदभाव समाप्त करने तथा बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों का शीघ्र, सकारात्मक एवं न्यायसंगत निराकरण किए जाने की मांग उठाई। UFBU जबलपुर इकाई के संयोजक अभिषेक कुमार सिन्हा ने कहा कि बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं। बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने में बैंककर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण योजनाओं सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने में बैंकिंग तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी बैंक कर्मचारी और अधिकारी लगातार योगदान दे रहे हैं।सिन्हा ने कहा कि बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। इनका शीघ्र एवं सकारात्मक समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित पक्षों से कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करने की अपेक्षा व्यक्त की।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यदि लंबित मुद्दों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण नहीं किया गया तो 26 अक्टूबर 2026 से बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।प्रदर्शन में प्रशांत खरे, चंदन कुमार, सुशील गुप्ता, प्रकाश रहंगडाले, दीपशिखा पटेल, एच.पी. पटेल, प्रमोद बोरकर, दीपक दीक्षित, विकास श्रीवास्तव, पंकज कुमार, आशीष खरे, तनिकेश सिंह, आकाश डोंगनिया, सचिन पटेल, मोहित रेंगटा, राकेश गुप्ता, संजय खरे, विनोद जोशी, दीपक देबकर, मिलिंद मरसकोले, संजीव कुमार, अरुण मिश्रा, दीपक तिवारी, प्रियंक तिवारी, राहुल गुहा, राकेश कमल गौतम एवं अग्निमेष दुबे सहित विभिन्न बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। UFBU जबलपुर इकाई ने राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा समस्त बैंकिंग बिरादरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

धान की जरूरत छह बोरी यूरिया, किसानों को नियम से मिल रही तीन से चार बोरी



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। धान की फसल के लिए किसानों को मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में यूरिया और पोटाश उपलब्ध कराने के दावों के बीच उर्वरक वितरण की व्यवस्था को लेकर किसानों की परेशानी सामने आ रही है। मप्र राज्य विपणन संघ कृषि भूमि के आधार पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। निर्धारित नियम के तहत पूरे सीजन में एक किसान को अधिकतम एक हेक्टेयर यानी करीब ढाई एकड़ भूमि के लिए कुल तीन से चार बोरी यूरिया देने की व्यवस्था है, जबकि किसानों के अनुसार धान की रोपाई से लेकर अंतिम छिड़काव तक एक हेक्टेयर में करीब छह बोरी यूरिया की जरूरत पड़ती है। सहकारी समितियों में निर्धारित नियम के अनुसार ही खाद का वितरण किया जा रहा है। किसानों को दी जाने वाली खाद का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि फसल की जरूरत के मुताबिक यदि अतिरिक्त यूरिया की आवश्यकता हो तो उन्हें निजी क्षेत्र से खाद खरीदनी पड़ रही है। इससे एक ओर सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता को लेकर दबाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर निजी दुकानों से महंगे दाम पर खाद खरीदने की मजबूरी बढ़ रही है। धान की अधिक पैदावार के लिए किसान फसल की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का उपयोग करना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से निर्धारित मात्रा और खेत में फसल की वास्तविक जरूरत के बीच अंतर होने से उन्हें अतिरिक्त खाद के लिए निजी विक्रेताओं पर निर्भर होना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक सहकारी समितियों से पर्याप्त खाद समय पर नहीं मिलने के कारण फसल के महत्वपूर्ण चरणों में उर्वरक की व्यवस्था करना चुनौती बन रहा है। रोपाई के बाद इन दिनों धान की फसल में छिड़काव का काम चल रहा है। जिले के कुछ बड़े किसान इस दौरान डीएपी और यूरिया का मिश्रित डोज इस्तेमाल कर रहे हैं। सिहोरा, मझौली, पाटन, पनागर, शहपुरा, बरगी, बरेला और मझगवां क्षेत्र की सहकारी समितियों में खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर हाल ही में मांग के अनुरूप यूरिया की आपूर्ति भी की गई है, जिससे वहां किसानों को कुछ राहत मिली है। किसानों का कहना है कि गांव के नजदीक स्थित सोसायटियों से खाद का वितरण परमिट के साथ नगद भुगतान पर किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि खाद की कालाबाजारी रोकने के प्रयास जरूरी हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इसका खामियाजा किसानों को न भुगतना पड़े। किसानों के अनुसार सहकारी समितियों से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें निजी दुकानों का रुख करना पड़ता है और यही स्थिति उनकी परेशानी बढ़ा रही है। सहकारी समितियों से समय पर पर्याप्त खाद नहीं मिलने का लाभ उठाकर कुछ निजी विक्रेताओं और कालाबाजारी करने वालों द्वारा मनमानी कीमत वसूलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। किसानों का आरोप है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक यूरिया की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हैं। हालांकि इन आरोपों की वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग की जांच और कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। उर्वरक वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के अनुसार डीएपी, ग्रोमोर और यूरिया के उत्पादन तथा आयात का बड़ा हिस्सा सरकारी व्यवस्था के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 75 से 80 प्रतिशत खाद सरकार के नियंत्रण वाली वितरण व्यवस्था के जरिए विपणन सहकारी समितियों और डबल लॉक केंद्रों से किसानों तक पहुंचती है। इसके बावजूद किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो घायल



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। पाटन-शहपुरा मार्ग पर नृत्य गोपाल मंदिर के पास तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही मोटरसाइकिल ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो लोग घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जबलपुर भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीराम कॉलेज के पीछे मदर टेरेसा, माढ़ोताल निवासी 32 वर्षीय संतोष मरावी ने पाटन थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। संतोष के अनुसार वह अपने साथियों कमलेश सिंह, रतनलाल मरावी और पंकज यादव के साथ मजदूरी के लिए पाटन खमदेही गया था। काम पूरा होने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 24 सितंबर की शाम करीब 7:10 बजे वे नृत्य गोपाल मंदिर के पास पहुंचे। तभी शहपुरा की ओर से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 एनडी 4176 के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए आगे चल रही रतनलाल मरावी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रतनलाल मरावी और बाइक पर पीछे बैठे पंकज यादव सड़क पर गिर गए। हादसे में दोनों के हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को उपचार के लिए जबलपुर भेजा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार हादसा तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होना बताया गया है। मामले में दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने घोषित किया इनाम

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय ने विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगद इनाम घोषित किया है। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कराने, उनके संबंध में सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को निर्धारित राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। पनागर थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 695/26 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 333, 191(2), 296(ए), 351(2), 119(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज है। इस प्रकरण में मझगवां निवासी 25 वर्षीय धर्मेन्द्र सिंह, 23 वर्षीय अस्सू नामदेव और 25 वर्षीय राज नामदेव फरार बताए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग तीन-तीन हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले या उनके बारे में ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम की राशि दी जाएगी, जिससे उनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। इसी तरह रांझी थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 830/25 में भी अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(1) के तहत प्रकरण दर्ज है। आरोपी पर सीमेंट की छत तोड़कर मकान में प्रवेश करने और वहां से सोने-चांदी के जेवर तथा वाईफाई कैमरा चोरी करने का आरोप है।

बाथरूम में गिरने से 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में बाथरूम में गिरने से 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज से मिली सूचना के अनुसार कटरा अधारताल निवासी नत्थूलाल कोरी 24 सितंबर को घर के बाथरूम में गिर गए थे। हादसे के बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। रात करीब 10 बजे नत्थूलाल कोरी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना अस्पताल की ओर से पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर गोहलपुर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस ने घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुजुर्ग के बाथरूम में गिरने के कारणों और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले में जांच के दौरान परिजनों के बयान लिए जाएंगे और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

जमीन के पैसों के विवाद में घर में घुसकर महिला से मारपीट



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन के सौदे से जुड़े पैसों के विवाद में एक महिला से घर में घुसकर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीछाया ड्यूपलेक्स, चेरीताल निवासी 40 वर्षीय श्वेता पाठक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब दो वर्ष पहले उनके पति स्वदेश पाठक का व्यौहारबाग निवासी शुभांशु उइके के साथ जमीन का सौदा हुआ था। तय समय पर राशि नहीं दिए जाने के कारण बाद में जमीन का सौदा रद्द हो गया था। शिकायत के अनुसार सौदा रद्द होने के बावजूद शुभांशु को कुछ राशि देना शेष थी। इसी रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में 25 सितंबर की सुबह करीब 10:15 बजे शुभांशु श्वेता पाठक के घर पहुंचा और उनके पति को बुलाने के लिए कहा। श्वेता ने पुलिस को बताया कि उस समय उनके पति घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने शुभांशु को इसकी जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि वह गेट धकेलकर घर के अंदर प्रवेश कर गया। इसके बाद उसने कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। महिला के मुताबिक विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ धक्का-मुक्की की और हाथ मोड़ दिया। इस दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वह कार से वहां से चला गया। घटना के बाद महिला ने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296(बी) और 351(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के तहत लोकसेवकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। राज्य शासन के सभी विभागों के लोकसेवकों में सेवा भाव की संस्कृति को आत्मसात करने तथा लोक केंद्रित प्रशासन की अवधारणा विकसित करने के उद्देश्य से कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के अंतर्गत ई-दक्ष केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत के मार्गदर्शन में जिला ई-गवर्नेंस कार्यालय द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में 21 से 25 सितंबर तक आयुष विभाग के आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसरों ने भाग लिया। आयुष विभाग के लोक सेवकों का प्रशिक्षण 29 सितम्बर तक आयोजित किया जाएगा। कर्तव्य कर्मयोगी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों में जन सेवा का भाव विकसित करना तथा उन्हें दक्ष, उत्तरदायी और सेवा भावी बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से लोक सेवकों को प्रशासनिक कार्यों में दक्ष बनाने के साथ ही जनहित और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अक्टूबर माह में विभिन्न विभागों के मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने-अपने विभाग के समस्त लोकसेवकों को 31 दिसम्बर तक प्रशिक्षित करेंगे।

18 नवंबर शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष दादा जगदीश यादव जी काआज जबलपुर नगर आगमन हुआ जिनका भव्य स्वागत किया गया उसके बाद घंटाघर कॉफी हाउस में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दादा जगदीश यादव जी ने अध्यक्षता की बैठक मे 18 नवंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया मुख्य आयोजन जबलपुर में आयोजित की जाएगी इसमें राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित होंगे दादा जगदीश यादव जी ने अपने बयान में कहां कि सन 1962 को भारत की सीमा रेजांगला पोस्ट में चीन के सैनिकों के साथ एक विशाल युद्ध चल रहा था उस युद्ध का नेतृत्व यादव अहीर के सैनिक कर रहे थे उन सभी सैनिकों को सेना अध्यक्ष द्वारा अपनी पोस्ट छोड़ने का निर्देश दिया गया परंतु वीर जवानों ने अपने आप को शहीद होना स्वीकार किया और अंतिम सांस तक चीन की सैनिकों के साथ युद्ध किया उसमें लगभग 120 सैनिक थे जिसमें से दो या चार लोगों ही बच पाए बाकी सभी का शहादत हुआ था शहादत होते-होते भी अपनी पोस्ट को सुरक्षित रखे थे ऐसे वीर योद्धाओं को याद करने के लिए 18 नवंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और साथ ही भारत सरकार से अहीर रेजिमेंट की मांग की गई ताकि नवयुवक यादव देश की सेवा के प्रति आस्था प्रकट किया जा सके और देश के प्रति समर्पण भाव से सेवा कर सके आज की इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संभागीय अध्यक्ष विजय यादव, जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव बड़डा, संजय यादव बसंत ता, शहर अध्यक्ष नरेश यादव, ग्रामीण अध्यक्ष मनोज यादव, राजेश यादव, दीपचंद यादव, महादेव पहलवान, डॉ गोविंद यादव, देवेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी जितेंद्र यादव , मोहन यादव, भागचंद यादव, विजय यादव, राकेश यादव जनपद सदस्य, रामकुमार यादव, राजाराम यादव, पार्थ यादव, राजा यादव, दिनेश यादव, अर्जुन यादव, सुरेंद्र यादव, श्रीमती रश्मि यादव, श्रीमती सविता यादव, कविता यादव, कंचन यादव, राकेश यादव, बबलू यादव, गोलू यादव, संदीप यादव, विवेक यादव, दीपक यादव, धर्मेंद्र यादव, सीताराम यादव, आदि सैकड़ो स्वजातिय बंधु उपस्थित थे।

युवक की हत्या के पाँच आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त कार, बाइक, कपड़े व पर्स जब्त



48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। प्रेम लाल कोल पिता समारू कोल उम्र 52 वर्ष निवासी सिवनी डोंगरी टोला थाना जैतहरी का रिपोर्ट लेख कराया की गणेश विसर्जन हेतु अपनी मोटर सायकल मे अपने साथी मिथुन कोल, राजेश यादव के साथ घर से निकला था, रात्रि 10 बजे मिथुन कोल अपने भाई के फोन मे गोवर्धन कोल के फोन से बताया कि तेजू का लडका सूरज अपने साथियो के साथ गोवर्धन को मारपीट कर रहे है, तब हम लोगो ने मिथुन कोल और राजेश कोल को अपने साथ ले जाकर गोवर्धन की पता तलाश किये तो वह नही मिला। लगातार पता तलाश करने पर गोवर्धन की मोटर साइकिल का टूटा हुआ क्लच केबिल और दोनो पैर की चप्पल मंडल के बगीचा मे मिला तथा मोटर सायकल, चप्पल से एक किलोमीटर दूरी पड़ा था। तेजराज राठौर से पूछने पर कोई पता नही चला, परिजन लगातार तलाश कर रहे हैं मगर गोवर्धन का पता नही चला, गोवर्धन का मोबाइल मिथुन के पास ही रह गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 140(3) बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। विवेचन के दौरान गोवर्धन कोल पिता प्रेमलाल कोल उम्र 22 वर्ष निवासी डोंगरी टोला सिवनी का शव बदनहाई डोंगरी सिवनी के जंगल मे झाडियो के बीच मिला। शव एवं घटना स्थल का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 103(1),238 बीएनएस 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(५) एससी एसटी का घटित करना पाये जाने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी को जानकारी दी गयी। घटना स्थल पर एफ.एस.एल. अधिकारियों एवं डाग स्काट पहुँचकर शव एवं घटना स्थल का निरीक्षण वीडियोग्राफी की गई व घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। मृतक गोवर्धन कोल का काले रंग का पैन्ट व जिसमे बेल्ट लगा हुआ सिर के पास रखा मिला, जिसे मौके पर जप्त किया गया व शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव का पी.एम. सीएचसी जैतहरी से करवाया गया। प्रकरण मे आरोपीगणो द्वारा अपराध धारा 140(3), 103(1),238 बीएनएस का घटित करना पाये जाने से धारा इजाफा कर मृतक गोवर्धन कोल अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने एवं आरोपी सूरज राठौर पिछडा वर्ग का राठौर जाति का होने से प्रकरण मे धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(५) एससी एसटी एक्ट बढाई गई प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पता तलास किया। आरोपी सूरज राठौर, राहुल सिंह राठौर, तेजराज राठौर, दिनेश गोड व राहुल राठौर सभी निवासी सिवनी को पकड़कर कर अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ करने पर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियो के घटना के वक्त पहने गये कपडे, घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकल, ईको कार, मृतक का पर्स आरोपियो द्वारा बताये स्थानो से जप्त किया गया है, आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है। मामले की विवेचना जारी रखते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपियो को न्यायिक रिमांड प्राप्त करने हेतु न्यायालय अनूपपुर पेश किया गया है।

शिक्षा के नाम पर मजाक, भाजपा विधायक की मांग, ढेड़ साल बाद भी नही जागी सरकार, नहीं मिला विद्यालय भवन

दैनिक रेवांचल टाइम्स उमरिया। पीएम श्री का तमगा लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोरहा में शिक्षा व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। जहाँ नर्सरी से 12वीं तक लगभग 900 छात्र अध्ययनरत हैं, उनका भविष्य भवन के बिना दांव पर लगा है। विद्यालय में कुल 16 कमरों और टीन के टपरों में बच्चों को कैद कर दिया गया है। जनपद करकेली की ग्राम पंचायत लोरहा में बच्चे जान हथेली पर रखकर जर्जर कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं। 50 प्रतिशत कक्षाएं आज भी टीन शेड में लगती हैं। न बाउंड्रीवॉल है, न पर्याप्त शौचालय, न पानी टंकी, न खेल मैदान। कंप्यूटर लैब का सामान धूल खा रहा है क्योंकि उसे रखने तक की जगह नहीं है। सरपंच रेखा कुशवाहा और प्राचार्य विनोद कुमार मिश्रा कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक गुहार लगाते-लगाते थक चुके हैं। तब ग्रामीण बांधवगढ़ भाजपा विधायक से मिले और विद्यालय भवन की समस्या बताई। इस पर विधायक



शिवनारायण सिंह लल्लू भैया ने 1 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक 181/25 लिखकर कलेक्टर उमरिया से भवन की अनुशंसा की थी। कलेक्टर कार्यालय ने 17 मई 2025 को पत्र क्रमांक 1718/राजस्व/2023 के माध्यम से फाइल जिला शिक्षा अधिकारी को सरका दी और उसके बाद फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। ग्राम पंचायत लोरहा के द्वारा 4 फरवरी, 21 फरवरी और 12 मार्च 2025 को लगातार आवेदन दिए गए। प्राचार्य ने 23 जुलाई 2025 को फिर सरपंच को पत्र लिखकर कमियां गिनाईं। 22.6670 हेक्टेयर नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिए आरसीएमसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन तक कर दिया गया, लेकिन सिस्टम टस से मस नहीं हुआ। सवाल सीधा है, जब पीएम श्री स्कूल में ही भवन नहीं है, तो शिक्षा की गुणवत्ता का ढिंढोरा किस बात का है? विधायक की अनुशंसा के बाद भी डेढ़ साल तक भवन स्वीकृत न होना, यह लापरवाही नहीं तो क्या है? अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भवन स्वीकृत नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर लिए 10 नमूने, रखरखाव में कमी पर 4 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी



दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। आयुक्त एवं नियंत्रक खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के आदेशानुसार होटल एवं रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर शहडोल श्री पार्थ जायसवाल के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी शहडोल डॉ. राजेश मिश्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा निरंतर निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा जयसिंहनगर एवं शहडोल क्षेत्र के 8 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल 10 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। जयसिंहनगर में आकांक्षा रेस्टोरेंट एवं पवनपुत्र रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। यहां रखरखाव एवं साफ-सफाई में कमी पाए जाने पर सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जा रहे तेल के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। सांदीपनी विद्यालय जयसिंहनगर में मध्यान्ह भोजन की जांच करते हुए चावल एवं नमक के नमूने लिए गए। वहीं कन्नोदी स्थित हनुमान ट्रेडर्स का निरीक्षण कर हल्दी एवं जीरा के नमूने जांच के लिए लिए गए। शहडोल में बाबूभाई स्वीट्स एवं सोनी रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर सुधार नोटिस जारी किया गया तथा पनीर एवं दही के नमूने जांच के लिए लिए गए। राजघराना ड्राई फ्रूट का निरीक्षण कर दालचीनी, लौंग एवं सौंफ के नमूने भी प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण के दौरान किचन, स्टोर एवं वाशिंग एरिया के रखरखाव में कमी पाए जाने पर कुल 4 प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना नोटिस जारी किए गए हैं। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट एवं नोटिस के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

समाजसेवी पार्षद पवन कुमार चीनी ने कैंसर की बीमारी परेशान महिला गौरी को दी आर्थिक सहायता

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। नगर परिषद बरगवां-अमलाई के वार्ड क्रमांक 10 देवहरा निवासी गौरी बैगा लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रही हैं। बीमारी के उपचार के साथ परिवार के सामने आर्थिक कठिनाइयां भी खड़ी हैं। ऐसे मुश्किल दौर में सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार चीनी ने परिवार की मदद के लिए आगे बढ़कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। गौरी बैगा की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद पवन कुमार चीनी ने उनके परिवार से मुलाकात की और इलाज में सहयोग के उद्देश्य से सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान उन्होंने गौरी बैगा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए परिवार को भरोसा दिलाया कि कठिन परिस्थितियों में जरूरतमंदों के साथ खड़ा होना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिजनों के अनुसार गौरी बैगा लंबे समय से उपचार



करा रही हैं। गंभीर बीमारी के चलते लगातार इलाज और दवाइयों का खर्च परिवार के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ऐसे समय में मिली आर्थिक सहायता से परिवार को उपचार संबंधी खर्चों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पवन कुमार चीनी द्वारा जरूरतमंद परिवारों की सहायता का यह पहला मामला नहीं बताया जा रहा है। इससे पहले बारिश के दौरान मकान क्षतिग्रस्त होने से परेशान परिवारों की जानकारी मिलने पर भी उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था। उनका कहना है कि बीमारी, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियों में सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सामाजिक सरोकार का वास्तविक उद्देश्य है। चीनी द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के अलावा विभिन्न सामाजिक आयोजनों में उनका सहयोग देखने को मिलता रहा है।

निमार्णाधीन सड़क का एक हिस्सा भरभराकर धंसने से गड्ढा में गिरा भैंसा, जेसीबी से बाहर निकाला

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। बीते दिन हुई तेज बारिश के बाद बिजुरी में निमार्णाधीन सड़क का एक हिस्सा अचानक भरभराकर धंस गया। सड़क धंसने से मौके पर बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें एक भैंसा जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा जनहानि वाला मामला सामने नहीं आया। जानकारी के मुताबिक, मौहरी से माइंस कॉलोनी को जोड़ने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। रातभर हुई बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। सुबह सड़क पर बने गड्ढे में एक भैंसा गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से



रेस्क्यू कर भैंसे को गड्ढे से बाहर निकाला गया। सड़क धंसने की घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई पुलिया और आरसीसी ह्यूम पाइप की व्यवस्था को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि बारिश के बाद सड़क का हिस्सा इतनी आसानी से कैसे धंस गया और निर्माण के दौरान जल निकासी एवं पुलिया की तकनीकी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। फिलहाल घटना के बाद संबंधित निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की जांच की जरूरत बताई जा रही है।



भिखारी बनकर डॉक्टर के घर पर दिनदहाड़े दीवार कूदकर चुराई मूर्ति, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। बुढ़ार थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति कथित तौर पर पागल और भिखारी के भेष में कई दिनों से इलाके में घूमता रहा। घर की रेकी करने के बाद मौका मिलते ही डॉक्टर के घर में घुस गया और वहां रखी एक मूर्ति चोरी कर फरार हो गया। चोरी की पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिले के बुढार थाना क्षेत्र आदर्श कॉलोनी निवासी डॉक्टर ए.के. लाला अपने घर में ही क्लिनिक संचालित करते हैं। घटना के समय डॉक्टर क्लिनिक खोलकर किसी काम से बाहर गए थे और घर के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। इसी दौरान एक व्यक्ति, जिसे स्थानीय लोग पिछले कुछ दिनों से भिखारी अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, घर के आसपास पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज में कथित चोर पहले घर के आसपास इधर-उधर घूमकर स्थिति का जायजा लेता नजर आ रहा है। कुछ देर तक रेकी करने के बाद जब उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो वह तेजी से गेट और दीवार को पार कर घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाने के बाद उसने सामान तलाशा, लेकिन जब कुछ खास हाथ नहीं लगा तो घर में रखी एक मूर्ति उठाई और उसी रास्ते से बाहर निकलकर फरार हो गया। भिखारी चोर की सब करतूत डाक्टर के घर में लगे सीसीटीवी कैद हो गई। डॉक्टर ए.के. लाला ने बताया कि एक व्यक्ति कुछ दिनों से इलाके में भिखारी के रूप में घूम रहा था, लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन मौका मिलते ही उसने घर में प्रवेश कर मूर्ति चोरी कर ली। उनका कहना है कि यदि घर में कोई कीमती सामान रखा होता तो वह उसे भी लेकर जा सकता था।

नदी में नहाने गया युवक हुआ लापता, एसडीईआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। राजेंद्रग्राम थाना क्षेत्र के मौहरी गांव में नदी में नहाने गया युवक अचानक नहाने के दौरान कुछ दूरी पर बह रही बमराड़ नदी में छलांग लगा दिया, जहां गहरे पानी में लापता हो गया है। घटना की सूचना युवक के साथ गए साले ने परिजनों को जहां परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने नदी का मामला देखते जिला मुख्यालय स्थित एसडीईआरएफ की टीम को सूचना देते रेस्क्यू के लिए बुलाया। हालांकि दूरी होने के कारण रेस्क्यू दल शाम मौके स्थल पहुंच कर पानी के तेज बहाव के बीच युवक को ढूंढने सर्चिंग अभियान शुरू किया लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण हो रहीं परेशानी के कारण ढूढ़ने का कार्य बंद कर दिया गया हैं। सुबह पुनः ढूंढने सर्चिंग अभियान शुरू किया जायेंगा। इसके पूर्व शाम को घटना स्थल पहुंची पुलिस स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों की मदद से खोजबीन कर रही थी। पुलिस ने बताया कि डूबने वाला युवक की पहचान 35 वर्षीय देव सिंह पिता गणेशा सिंह उड़ाली निवासी ग्राम बराँझ थाना करनपठार अनूपपुर के रूप में हुई है। युवक कुछ दिन पूर्व ही राजेंद्रग्राम स्थित अपने ससुराल मौहरी गांव आया था। ससुराल से ढाई किलोमीटर दूर अपने साले 28 वर्षीय बेल सिंह पिता ललुआ सिंह के साथ बमराड़ नदी के पास पतली नाला के रूप में बह रहे देवरी डवरा में नहा रहा था, साबुन लगाने के उपरांत वह अचानक वहां से उठकर बमराड़ नदी की ओर बढ़ा और नहाने के लिए कूद गया। जिसके बाद वह नदी से वापस नहीं निकला है। नदी में पानी का बहाव तेज है। वहीं अनूपपुर मुख्यालय से सूचना प्राप्ती के बाद तत्काल जिला प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में 03 एसडीईआरएफ एवं 04 होमगार्ड जवान घटनास्थल के लिए रवाना हुई। बताया जाता है कि घटनास्थल की दूरी लगभग 80 किमी है।

बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज युवक शराब के नशे में चढ़ा ट्रांसफार्मर पर, कर्मचारियों को दी गाली

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। बिजली का कनेक्शन काटे जाने से नाराज एक युवक ने शराब के नशे में जान की परवाह किए बिना विद्युत सब-स्टेशन परिसर में पहुंचा और ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर बैठ गया, इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए घंटों हंगामा करता रहा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला अमलाई थाना क्षेत्र के रूंगटा-साबो स्थित एसईसीएल शारदा ओसीएम की बंद पड़ी खदान की कॉलोनी के सब-स्टेशन का है। रूंगटा निवासी बबलू केवट अपने क्वार्टर की बिजली काटे जाने से नाराज था। बताया जा रहा है कि लगातार बिजली गुल होने को लेकर भी वह परेशान था। इसी दौरान शराब के नशे में वह सब-स्टेशन पहुंच गया और वहां लगे ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर बैठ गया। वायरल वीडियो में युवक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बैठा दिखाई दे रहा है। वह विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर गाली गलौज करता नजर आ रहा है। सुरक्षा को देखते हुए कर्मचारी वहां से दूर हट गए। बताया जा रहा है कि युवक के ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ने के बाद उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफॉर्मर की बिजली सप्लाई लाइन काट दी गई थी, इसके बाद भी युवक काफी देर तक ऊपर बैठकर हंगामा करता रहा। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद वह आखिरकार नीचे उतरा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि संवेदनशील विद्युत परिसर में युवक प्रवेश कैसे कर गया। सब स्टेशन की सुरक्षा के लिए वहां क्या इंतजाम किए गए हैं?

संपादकीय

वोट को लेकर जन-आंदोलन

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय जन-आंदोलन का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने राज्यों की राजधानियों में विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भी 29 सितंबर को तय हुई है। शायद कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा! ह्यराजनीतिक कॉकरोचोंह्न ने भी सीईसी का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन की धमकी दी है। विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने सीईसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और जेल में डालने की पुरजोर मांग की है। हालांकि दिसंबर, 2023 में चुनाव आयोग संबंधी कानून में संशोधन कर सीईसी, पूर्व सीईसी और चुनाव आयुक्तों को किसी भी तरह के केस और जेल भेजने की सजा से ह्यकानूनी छूटह्न दी गई थी। उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह संशोधन संसद में पारित किया गया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेता इस संसदीय संशोधन को जानते होंगे! फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने सीईसी को ह्यगद्दारह्न और ह्यदेशद्रोहीह्न करार दिया है। उनके इस्तीफे और ह्यसरकारी गवाहह्न बनने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष को यकीन है कि ऐसे ह्यअपराधीह्न को सजा जरूर मिलनी चाहिए। विपक्ष का कथित ह्यइंडिया ब्लॉकह्न संसद के दोनों सदनों में, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, ह्यमहाभियोगह्न प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। इसी साल मार्च-अप्रैल में भी ह्यमहाभियोगह्न का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति ने खारिज कर दिया था। लेकिन आसार पुख्ता होते जा रहे हैं कि शहर, कस्बा, गांव और गली-गली के स्तर पर देश का आम नागरिक ह्यविशेष गहन पुनरीक्षणह्न (एसआईआर) का ही बहिष्कार कर दे! चूंकि उनके वोट काटे जा रहे हैं, लिहाजा संविधान में दिए मताधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि संविधान का ही उल्लंघन होता रहा, तो लोकतंत्र किस काम का..? लोकतंत्र की बुनियाद ही आम मतदाता का वोट और जनादेश है। यदि वोट से संसद, विधानसभा, सरकारें नहीं चुनी जा सकतीं, तो वोट ही बेमानी किया जा रहा है। जन-आंदोलन इस मताधिकार को हासिल करने और एसआईआर की आड़ में ह्यचुनावी साजिशह्न को पराजित करने को लेकर उग्र और देशव्यापी होगा। अब यह लोकतंत्र-समर्थक लामबंदी की ही अग्नि-परीक्षा है कि वे आम नागरिक को कितना समझा पाते हैं कि ह्यवोट चोरीह्न के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं? राहुल गांधी और विपक्षी नेता अभी तक ह्यवोट चोरीह्न के आरोप लगा रहे थे, लिहाजा उन्हें ह्यक्षुद्र राजनीतिह्न माना जा रहा था। अब चुनाव आयोग के ही दो संवैधानिक चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों और सवालों से लगभग पुष्टि हो रही है कि ह्यवोट चोरीह्न ही नहीं, वोट देने का मौलिक अधिकार भी छीना जा रहा है। एक अभियान के तहत करीब 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम काट देना कोई सामान्य घटना नहीं है। गोवा जैसे छोटे-से राज्य का उदाहरण सार्वजनिक हुआ है कि 97 मतदाताओं के नाम और ब्यौरे ह्यसहीह्न पाए गए, लेकिन राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी 8 बार ई-मेल कर और फोन पर ब्रीफ करने के बावजूद उन 97 नामों को मतदाता-सूची में जुड़वा नहीं सका। इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। उन मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार छिन गए, वे वोट नहीं दे सकेंगे, ऐसे लोकतंत्र का क्या करेंगे हम? यह कैसी प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य के सीईओ की भी आयोग के आईटी सिस्टम तक पहुंच नहीं है! यकीनन अब यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी तक भी जाएगा। मुद्दा यह नहीं है कि सीईसी के पद पर ज्ञानेश का चयन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ह्यअसहमतिह्न को किनारे कर दिया गया। सरकारें ऐसे ही काम करती हैं और चयन प्रधानमंत्री के स्तर पर ही होता रहा है। इसमें साजिश क्या है? चूंकि अब चुनाव आयोग का भीतरी यथार्थ बेनकाब हुआ है, किसी ने भी उसका खंडन नहीं किया है, किसी ने भी सफाई नहीं दी है या अदालत में उसे चुनौती दी है, अंततः सीईसी ज्ञानेश को ही ह्यखलनायकह्न माना जा रहा है। यदि देश भर में जन-आंदोलन फैलता है, तो प्रधानमंत्री कब तक सीईसी को बचा पाएंगे? यह भाजपा-कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, देश के आम नागरिक के मताधिकार का सवाल है और यह राष्ट्रीय सरोकार का मुद्दा बन सकता है। विपक्ष का गंभीर आरोप है कि केंद्र तथा कई राज्यों में सरकार निर्माण में चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण रही है। अगर यहां पर निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते, तो निश्चय ही भाजपा की सरकारें न बनतीं। राहुल गांधी का मानना है कि इन जगहों पर दोबारा से निष्पक्ष चुनाव करवाए जाने चाहिएं। उनकी यह भी मागं है कि इस मसले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकारी गवाह बनना चाहिए। कांग्रेस कई राज्यों में इस मसले को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रही है।

कच्चे तेल की कीमतें बनीं दुनिया का सबसे बड़ा अप्रत्याशित आर्थिक कारक, बढ़ी बाजार की अनिश्चितता

कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग जिसके खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही थी वह पिछले कुछ सप्ताहों से फिर जोर पकड़ रही है। अगस्त में यह 80-90 डॉलर प्रति बैरल के करीब था। परंतु अब इस तरह का बदलाव अस्वाभाविक नहीं रह गया है। तेल और गैस बाजार अब अतीत के कई दशकों की तुलना में कहीं अधिक अप्रत्याशित हो चुका है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा और सबसे अप्रत्याशित रुझान लोकलुभावन नीतियों पर चलने वाले और अधिनायकवादी नेताओं का व्यवहार है। पहला बड़ा झटका 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के फैसले से लगा। इसके चलते प्राकृतिक गैस की कीमतें आसमान छू गईं। इसके बावजूद काफी मुश्किल से हासिल हुई स्थिरता लौटती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी साल की शुरूआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला कर लिया। दोनों ही मामलों में उम्रदराज नेता, चाहे वे अलग-थलग हों या आसानी से प्रभावित होने वाले, वे ऐसा मानते दिखाई दिए कि दूसरा पक्ष जवाबी कार्रवाई में सक्षम नहीं होगा और युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि पुतिन ने रूसी तेल और गैस के निर्यात पर लगाए जाने वाले व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले प्रतिबंधों को अपने आकलन में शामिल ही नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जब कोई विश्व नेता जानबूझकर बाजारों में खलल नहीं डाल रहा था तब बाजार बहुत अच्छी तरह काम कर रहे थे। उदाहरण के लिए 2024 के अंत में ज्यादातर अनुमान यह थे कि अगले साल यानी 2025 के दौरान तेल की कीमत करीब 75 डॉलर प्रति बैरल रहेगी लेकिन हकीकत में यह 68 डॉलर रही। 2026 के लिए तेल की कीमत का अनुमान करीब 61 डॉलर प्रति बैरल था लेकिन पूरे साल के दौरान वायदा बाजार में यह आंकड़ा इसके दोगुने तक पहुंचने की आशंका पैदा हुई है। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में



लगाए गए प्रतिबंधों और रूस के सामने अपने तेल और गैस को बाजार तक पहुंचाने में बनी हुई मुश्किलों के अलावा अब हूती विद्रोहियों के कारण लाल सागर के भी बंद होने की आशंका के बीच पूवार्नुमान लगाने वालों को कई अन्य जटिलताओं को भी अपने आकलन में शामिल करना पड़ता है। साल की दूसरी तिमाही में चीन ने कच्चे तेल का आयात प्रतिदिन करीब 35 लाख बैरल घटा दिया जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 30-32 फीसदी की गिरावट है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका मतलब यह है कि चीन के पास कच्चे तेल का वाणिज्यिक और रणनीतिक भंडार पहले के अनुमान से कहीं अधिक है। दूसरों का मानना है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था के व्यापक विद्युतीकरण का लाभ उठाते हुए तेल की मांग घटा रहा है या रूस के उस तेल और गैस को आयात करने के नए रास्ते तलाश रहा है जो अन्यथा बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में यह पता नहीं है कि चीन कितने समय तक तेल के आयात को इस तरह दबाए रख सकता है या फिर रणनीतिक रूप से मांग में इस मौजूदा कमी का कोई स्थायी परिणाम यह होगा कि चीन की मुख्य भूमि की तेल आयात मांग हमेशा के लिए कम हो जाए। आगे की स्थिति को देखते हुए कई अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन (ओपेक) की स्थिति पहले से ही मुश्किल में थी क्योंकि 1970 के दशक में इसकी स्थापना के बाद कुछ ऐसे देश बड़े तेल निर्यातक बन गए जो ओपेक का हिस्सा नहीं थे जैसे अमेरिका। इस साल की शुरूआत में संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक से बाहर होने का फैसला किया। इससे सऊदी अरब के प्रभुत्व वाले इस समूह की भविष्य में तेल की कीमतें तय करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। फिर भी कीमतों पर ओपेक का पर्याप्त प्रभाव बना हुआ है। उसके पास एक ऐसा लक्ष्य है जो वैश्विक बाजार में तेल की संतुलित कीमत को प्रभावित करता है। लेकिन वह लक्ष्य क्या है? संभवतः वह सऊदी अरब की आंतरिक राजनीति की आगे की दिशा से तय होगा। हालांकि प्राथमिकता उन विभिन्न तरीकों को आगे बढ़ाने की होगी जिनके जरिये सऊदी अरब की सरकार अपने नागरिकों तक आय पहुंचाती है क्योंकि राजनीतिक स्थिरता काफी हद तक उसके कल्याणकारी राज्य के विस्तार पर निर्भर हो सकती है। सऊदी अरब को अपना बजट संतुलित करने के लिए तेल की कीमत कितनी रखनी चाहिए इस बारे में अनुमान बहुत अलग-अलग है। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान था कि यह कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल होनी चाहिए। 2024 में उसी संस्था ने इसे 100 डॉलर के करीब माना, जबकि 2025 में आईएमएफ का अनुमान 90 डॉलर प्रति बैरल था। इस संभावना को भी ध्यान में रखना होगा कि तेल के कुछ अन्य स्रोतों से फिर से उत्पादन शुरू हो जाए। यदि ईरान के साथ कोई समझौता होता है तो जाहिर है कि बाजार में केवल होर्मुज स्ट्रेट के जरिये अरब देशों का तेल बाहर आने की स्थिति ही नहीं बनेगी, बल्कि ईरान के तेल क्षेत्रों में भी उत्पादन उस स्तर तक पहुंच सकता है, जो एक दशक से अधिक समय से नहीं देखा गया है। वेनेजुएला की बात करें तो आर्थिक पतन और अंतरराष्ट्रीय अलगाव से पहले यह दक्षिण अमेरिकी तेल निर्यातक देश प्रतिदिन 30 लाख बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता था। 2025 में उसका निर्यात घटकर 8 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम रह गया। आखिर वह समझौता क्या है जिसे ट्रंप ने वेनेजुएला पर लागू किया है? यदि वहां से प्रतिदिन करीब 10 लाख बैरल अतिरिक्त तेल बाजार में आने लगे तो इसका कीमतों पर असर पड़ेगा। सबसे महत्त्वपूर्ण संभावना यह है कि मौजूदा संकट कच्चे तेल से हटकर ऊर्जा के अन्य स्रोतों चाहे वे नवीकरणीय ऊर्जा हों या परमाणु ऊर्जा की ओर बदलाव को तेज कर सकता है। इस बदलाव का पूरा असर सामने आने में दशकों लग सकते हैं लेकिन इसके प्रभाव हमें उससे कहीं पहले दिखाई देने लग सकते हैं। भारत ने मौजूदा उथलपुथल का सामना अधिकांश देशों की तुलना में बेहतर ढंग से किया है। लेकिन तथ्य यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर या बदतर दिशा में प्रभावित करने की सबसे अधिक क्षमता रखने वाले दो कारक मॉनसून की स्थिति और तेल की कीमत हैं। देश में इस समय अधिकारी यह तय करने में लगे होंगे कि 2027 के केंद्रीय बजट तैयार करते समय तेल की कीमत का अनुमान क्या हो। एक बात को लेकर हम निश्चित हो सकते हैं कि अपनी किसी गलती के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण उनका अनुमान गलत साबित होने वाला है।

15 दिनों तक श्रद्धा से होंगे पूर्वजों के तर्पण और श्राद्ध

पूर्वजों के स्मरण और श्रद्धा का पर्व, घर-घर होगी तर्पण, पिंडदान और अन्नदान की परंपरा

दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मंडला। हिंदू धर्म में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने वाला पितृ पक्ष इस वर्ष 27 सितंबर से शुरू होगा। अगले करीब 15 दिनों तक श्रद्धालु अपने दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करते हुए विधि-विधान से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और अन्नदान करेंगे। पितृ पक्ष को भारतीय संस्कृति में पूर्वजों के प्रति सम्मान और परिवार की परंपराओं से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान परिवार के लोग अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में श्रद्धापूर्वक किए गए तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य से पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है। कई परिवारों में ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, जरूरतमंदों को अन्न-वस्त्र दान तथा अन्य धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं।

हर दिन का अपना धार्मिक महत्व

पितृ पक्ष में प्रत्येक तिथि का अपना महत्व माना जाता है। परिवार के दिवंगत सदस्यों की मृत्यु तिथि के अनुसार संबंधित तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। जिन लोगों को पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके लिए भी परंपरा में विशेष तिथियों का उल्लेख मिलता है। इसी कारण इन दिनों मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहती है।

नई पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ने का अवसर

पितृ पक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार की नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों और पारिवारिक परंपराओं से परिचित कराने का अवसर भी माना जाता है। बुजुर्गों द्वारा बच्चों को परिवार के दिवंगत सदस्यों की स्मृतियां और उनके जीवन से जुड़े प्रसंग सुनाए जाते हैं। इस तरह पितृ पक्ष स्मरण, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों की परंपरा को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। श्रद्धा का संदेश यही है कि जिन पूर्वजों ने परिवार और समाज के निर्माण में योगदान दिया, उन्हें याद किया जाए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए और जरूरतमंदों की सेवा के माध्यम से मानवता का भाव मजबूत किया जाए।

राशिफल

मेष राशि :- कार्य लाभ में आशानुकूल सफलता का हर्ष होगा रुके कार्य बनेंगे।

वृष राशि :- योजना पूर्ण हो, शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो, सोचे हुए कार्य अवश्य बनेंगे।

मिथुन राशि :- कार्य व्यवसाय में थकावट बेचैनी कुछ असफलता के साधन अवश्य ही बनेंगे।

कर्क राशि :- दैनिक व्यवसाय गति मंद रहे, असमर्थता का वातावरण बना ही रहेगा।

सिंह राशि :- आलोचना से बचियें, कार्य कुशलता से पूर्ण संतुष्ट तथा संतोष बना ही रहेगा।

कन्या राशि :- भोग ऐश्वर्य में समय बीते, शारीरिक थकावट बेचैनी कार्य में बढ़ेगी, ध्यान रखें।

तुला राशि :- मित्र वर्ग विशेष फलप्रद रहे, आशानुकूल सफलता से संतोष होगा।

वृश्चिक राशिः- मित्र वर्ग विशेष फलप्रद रहे, कार्य में सफलता प्राप्त होगी, रुके कार्य अवश्य बनेंगें।

धनु राशि :- तनाव पूर्ण वातार्लाप चलनी ही रहेगी तथा सुख वर्धक योग अवश्य ही बनेगा।

मकर राशि :- कार्यवृत्ति में सुधार, सामाजिक कार्य में मान प्रतिष्ठा अवश्य ही बनेगा।

कुंभ राशि :- कार्य व्यवसाय गति मंद चोट आदि का भय होगा तथा मानसिक तनाव बनेगा।

मीन राशि :- आशानुकूल सफलता का हर्ष बिगड़े कार्य की योजना अवश्य ही बनेगा।

डाइट में फाइबर की कमी होने पर शरीर देता है ये संकेत

नई दिल्ली, एजेंसी। फाइबर शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों में शामिल है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ पेट की सेहत बेहतर बनाए रखने और मल त्याग को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाइट में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं होने पर शरीर कई तरह के संकेत दे सकता है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कैलिफोर्निया में रहने वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताया है, जो डाइट में फाइबर की कमी की ओर इशारा कर सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार, खाना खाने के तुरंत बाद दोबारा भूख लगना भी डाइट में पर्याप्त फाइबर नहीं होने का संकेत हो सकता है। फाइबर युक्त भोजन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। ऐसे में यदि भोजन के थोड़ी देर बाद ही भूख लगने लगे, तो यह देखा जाना चाहिए कि भोजन में फाइबर की पर्याप्त मात्रा शामिल है या नहीं। फाइबर की कमी का एक अन्य संकेत खाना खाने के बाद ब्लड शुगर का तेजी से बढ़ना हो सकता है। डॉक्टर सेठी के मुताबिक घुलनशील फाइबर काबोर्हाइड्रेट के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इससे भोजन के बाद ग्लूकोज के स्तर में होने वाली तेज वृद्धि को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए भोजन में फाइबर की पर्याप्त मात्रा का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। डाइट में फाइबर की कमी होने पर शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने की समस्या भी सामने आ सकती है। डॉक्टर सेठी के अनुसार फाइबर की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने पर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना हृदय से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को बढ़ाने वाला कारक माना जाता है। मल का सख्त होना भी



फाइबर की कमी का प्रमुख संकेत हो सकता है। डॉक्टर सेठी ने बताया कि फाइबर मल की मात्रा बढ़ाने और उसमें पानी बनाए रखने में मदद करता है। इससे मल त्याग आसान हो जाता है। भोजन में फाइबर की कमी होने पर मल सख्त हो सकता है और इसे बाहर निकालने में परेशानी हो सकती है। फाइबर की कमी का संबंध केवल कब्ज से ही नहीं है, बल्कि मल के ढीले होने की स्थिति में भी इसकी भूमिका हो सकती है। डॉक्टर के अनुसार घुलनशील और जेल बनाने वाला फाइबर पानी को अवशोषित कर सकता है, जिससे ढीले मल को कुछ हद तक सख्त करने में मदद मिल सकती है। इसलिए पाचन तंत्र को संतुलित रखने में फाइबर की भूमिका महत्वपूर्ण है। काबोर्हाइड्रेट वाला भोजन करने के बाद तुरंत थकान महसूस होना भी फाइबर की कमी से जुड़ा संकेत हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार भोजन के बाद इस तरह की थकान ब्लड शुगर में अचानक गिरावट यानी शुगर क्रैश का संकेत हो सकती है। खाने में फाइबर की कमी होने पर काबोर्हाइड्रेट के अवशोषण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण भोजन के बाद इस तरह की स्थिति महसूस हो सकती है। नियमित रूप से मल त्याग नहीं होना भी डाइट में फाइबर की कमी का संकेत माना जाता है। फाइबर की मात्रा बढ़ाने से कब्ज से पीड़ित लोगों में मल त्याग की आवृत्ति में सुधार हो सकता है। डॉक्टर सेठी के अनुसार कब्ज की स्थिति में पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और सही प्रकार तथा पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेने से मल की बनावट और नियमितता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

ज्यादा चाय पीना इन लोगों के लिए हो सकता है नुकसानदायक

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय घरों में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरूआत चाय की गर्म चुस्की के साथ होती है। चाय कई लोगों की रोजमर्रा की आदत का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट शुभम वत्स के अनुसार, कुछ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में चाय पीने से बचना या इसकी मात्रा सीमित रखना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा अधिक चाय पीने से पेट और शरीर पर कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकते हैं। चाय में मौजूद टैनिन इसे गहरा रंग और कड़क स्वाद देते हैं। इनसे कुछ समय के लिए ऊर्जा महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों को थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। टैनिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन पेट की अंदरूनी परत में जलन पैदा कर सकता है। इससे अम्लता और पेट में जलन जैसी समस्या हो सकती है। चाय में दूध और चीनी मिलाने से उसमें कैलोरी और शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक शर्करा का सेवन शरीर में इंसुलिन के स्तर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए चाय पीने वालों को उसमें डाली जाने वाली चीनी की मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। दिन में कई बार अधिक चीनी वाली चाय पीने की आदत शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग यानी जीईआरडी से परेशान लोगों को चाय के सेवन को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर गंभीर स्थिति में चाय से बचने की सलाह दी जाती है।



चाय कुछ लोगों में अम्लता और सीने में जलन जैसी शिकायतों को बढ़ा सकती है। ऐसे लोगों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी चाय का सेवन सीमित रखना चाहिए। चाय में मौजूद कैफीन गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंच सकता है। इसी तरह शरीर में लौह तत्व की कमी होने पर भी चाय का सेवन कम करने या बंद करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को अत्यधिक चिंता या घबराहट की समस्या रहती है, उन्हें अधिक कैफीन वाली चाय से बचना चाहिए। जिन लोगों को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, उन्हें भी रोजाना दो कप से अधिक चाय नहीं पीने की सलाह दी गई है।

सप्ताहांत में ही व्यायाम करने वालों को भी रखना चाहिए इन बातों का ध्यान

नई दिल्ली, एजेंसी। आज की व्यस्त जिंदगी में कई लोग पूरे सप्ताह कार्यालय, घर और दूसरी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में व्यायाम के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग सोमवार से शुक्रवार तक बिल्कुल व्यायाम नहीं करते और शनिवार-रविवार को एक साथ लंबे समय तक कसरत करके इसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। बेंगलुरु स्थित स्पर्श अस्पताल के हृदय रोग विभाग के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर आर.एस. वेंकटेसुलु के अनुसार, इस तरह की गतिविधि को आम तौर पर ह्यसप्ताहांत योद्धाह्न गतिविधि कहा जाता है। यदि पूरे सप्ताह रोजाना व्यायाम नहीं किया जाता है, तो सप्ताहांत में की गई शारीरिक गतिविधि बिल्कुल कुछ नहीं करने से बेहतर है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि सप्ताह के बाकी दिनों में लगातार बैठे रहें। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद अचानक बहुत अधिक और तेज व्यायाम करने से मांसपेशियों में चोट लग सकती है। कुछ लोगों में इससे हृदय पर अचानक दबाव बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि रोजमर्रा की दिनचर्या में थोड़ी शारीरिक गतिविधि जरूर शामिल हो। डॉक्टर के अनुसार प्रतिदिन करीब 30 मिनट पैदल चलना एक आसान विकल्प हो सकता है। नियमित रूप से चलने की आदत शरीर को सक्रिय रखने में मदद करती है और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत को कम किया जा सकता है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली वायवीय शारीरिक गतिविधि करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा 75 मिनट तेज तीव्रता वाली गतिविधि भी एक विकल्प हो सकती है। इसे सप्ताह के अलग-अलग दिनों में बांटकर किया जा सकता है, जिससे शरीर पर अचानक अधिक दबाव पड़ने से बचा जा सके। रोज करीब 30 मिनट तेज गति से पैदल चलना हृदय को स्वस्थ रखने के आसान विकल्पों में शामिल है। इसके साथ ही सप्ताह में कम से कम दो दिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली कसरत को भी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी जाती है। इससे शरीर की सक्रियता बनाए रखने में मदद मिलती है। तेज गति से पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना और साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां भी रोजमर्रा की शारीरिक सक्रियता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने के दौरान बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए उठकर चलना या सक्रिय रहना भी उपयोगी है। छोटी अवधि की ऐसी गतिविधियां पूरे दिन शरीर को सक्रिय रखने में मदद करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल शनिवार और रविवार को ही व्यायाम करने का समय है, तो उसे इन दिनों शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। हालांकि, सप्ताह के दूसरे दिनों में भी धीरे-धीरे छोटी अवधि की गतिविधियां अपनी दिनचर्या में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अचानक सप्ताहांत में बहुत अधिक कसरत करने के बजाय नियमित और संतुलित गतिविधि को प्राथमिकता देना बेहतर है।



पहले बरगी बांध परियोजना ने उजाड़े

घर-बार, अब अधिक जलभराव से विस्थापितों की जिंदगी पर संकट

बीजासेन में घरों तक पहुंचा पानी

प्लेग्राउंड डूबा, ग्रामीण बोले–पहले जमीन छूटी, अब सुरक्षित ठिकाना भी नहीं

एक बार बांध के लिए उजड़े अब बढ़ते पानी ने फिर घेरा

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- बरगी बांध परियोजना के लिए कभी अपने घर और जमीन छोड़ने वाले विस्थापित परिवारों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बरगी जलाशय में बढ़ते जलभराव के चलते डूब क्षेत्र से लगे गांवों में एक बार फिर पानी लोगों की जिंदगी में परेशानी बनकर पहुंच रहा है। घंसौर तहसील के बीजासेन गांव में जलाशय का पानी आबादी क्षेत्र तक पहुंच गया है। घरों के आसपास पानी भरने के साथ बच्चों का खेल मैदान भी डूब चुका है। विस्थापित परिवारों का कहना है कि पहले बरगी बांध परियोजना के निर्माण के दौरान जिंदगी उजड़ गई और अब जलाशय में अधिक जलभराव नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। उनका कहना है कि विस्थापन के बाद कई परिवार जलाशय के आसपास पहाड़ियों और वनभूमि वाले क्षेत्रों में बसने को मजबूर हुए। ऐसे में बारिश और जलस्तर बढ़ने के दौरान सुरक्षित जीवन को लेकर चिंता और बढ़ जाती है।







घर के दरवाजे तक पानी, रात में जहरीले जीव-जंतुओं का डर

बीजासेन निवासी चन्नी बर्मन ने बताया कि ग्रामीण दिन-रात डर के माहौल में रहने को मजबूर हैं। पानी बढ़ने पर कच्चे मकानों के कमजोर होने और उनके क्षतिग्रस्त होने की चिंता बनी रहती है। गांव के धन्नू बर्मन ने बताया कि शौचालय सहित कई स्थान पानी में डूब चुके हैं। इससे ग्रामीणों के सामने दैनिक जरूरतों को पूरा करने की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं झनकू साहू ने बताया कि रात में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दरवाजे तक पानी लगा रहने के कारण जहरीले जीव-जंतुओं के घरों में पहुंचने का डर बना रहता है।

बच्चों का खेल मैदान डूबा, सुरक्षा की चिंता

पालक-शिक्षक संघ के अध्यक्ष भुवन बर्मन ने बताया कि बच्चों के खेलने का मैदान पानी में डूब चुका है। इससे बच्चों के फिसलने या पानी में चले जाने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने जलभराव वाले क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाने की मांग की है।

विस्थापित संघ ने उठाए बांध प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल

बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ के राजकुमार सिन्हा ने कहा कि विस्थापितों के गांव बरगी जलाशय के अधिकतम भराव स्तर 422.76 फीट से ऊपर बसे हुए हैं। इसके बावजूद आबादी क्षेत्र में पानी पहुंचना गंभीर चिंता का विषय है। सिन्हा के अनुसार, बांध के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले पानी की स्थिति का समय रहते आकलन कर जलाशय के गेट खोलकर पानी की निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संघ का आरोप है कि समय पर जल निकासी नहीं होने से विस्थापित परिवारों को बार-बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

हर बार बढ़ता पानी, हर बार वही परेशानी

विस्थापित संघ का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक जलभराव के कारण मकानों में पानी पहुंचने और खेतों में खड़ी फसलों के प्रभावित होने की स्थिति सामने आती रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हर वर्ष जलस्तर बढ़ने के बाद ही प्रभावित परिवारों की चिंता की जाएगी? पहले बांध के लिए घर और जमीन छोड़ी, फिर विस्थापन के बाद नया ठिकाना बनाया और अब बढ़ते जलभराव ने उसी जीवन को फिर असुरक्षित बना दिया है। विस्थापित परिवारों की परेशानी केवल मौजूदा जलभराव तक सीमित नहीं है, बल्कि वे स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

उच्चस्तरीय जांच और नुकसान के सर्वे की मांग

बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। संघ का कहना है कि यदि जल प्रबंधन में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन से प्रभावित गांवों में मकान, फसल और अन्य नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर पात्र परिवारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है। विस्थापितों का कहना है कि उन्हें हर साल पानी बढ़ने के साथ डर के साए में न रहना पड़े, इसके लिए जल प्रबंधन के साथ प्रभावित गांवों की सुरक्षा और स्थायी पुनर्वास व्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान देना होगा।

सामाजिक, धार्मिक और खेल गतिविधियों में सक्रिय भूमिका के लिए पहचान रखता है सद्भाव ग्रुप

सद्भाव ग्रुप के नए अध्यक्ष बने साकेत कपूर



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- सद्भाव ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष नवल सिंह ठाकुर का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आयोजित बैठक में शहर के प्रतिष्ठित आदर्श विकास केंद्र के प्रोपराइटर साकेत कपूर को सद्भाव ग्रुप का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। बैठक में ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों करम सिंह बघेल, अभिराज सिंह ठाकुर, ऋषिकांत त्रिवेदी, आशीष गोलू सक्सेना, विनीत जायसवाल एवं राजेश यादव ने अध्यक्ष पद के लिए साकेत कपूर के नाम का प्रस्ताव रखा। उपस्थित सदस्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष नवल सिंह ठाकुर सहित वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया। वक्ताओं ने विश्वास जताया कि साकेत कपूर के नेतृत्व में सद्भाव ग्रुप की सामाजिक, धार्मिक एवं खेल गतिविधियों को और विस्तार मिलेगा।

खेल गतिविधियों से जुड़ा रहा है कपूर का सफर

साकेत कपूर लंबे समय से सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के साथ खेल जगत से जुड़े रहे हैं। उन्होंने तिलक स्कूल से खेल गतिविधियों की शुरूआत की। इसके बाद जिले के प्रतिष्ठित गजानन स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके वे वर्तमान में अध्यक्ष हैं। स्वयं फुटबॉल एवं क्रिकेट के खिलाड़ी रहे कपूर सद्भाव ग्रुप के डबल विकेट सहित विभिन्न खेल आयोजनों में भी सक्रिय सहभागिता निभा चुके हैं। सद्भाव ग्रुप द्वारा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते रहे हैं। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद साकेत कपूर ने ग्रुप की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की बात कही। ग्रुप की ओर से बताया गया कि साकेत कपूर के ताजपोशी कार्यक्रम की तिथि शीघ्र निर्धारित कर सदस्यों को सूचित की जाएगी।

जहां शिक्षा की पहुंच नहीं, वहां एकल विद्यालय बने उम्मीद की किरण – डॉ. के.के. चतुर्वेदी

नवरात्र तक अंचल स्तर पर 56 सदस्यीय समितियों के गठन का लक्ष्य, जनसहयोग बढ़ाने पर जोर

एकल विद्यालयों के विस्तार को लेकर सतपुड़ा भाग की संभाग स्तरीय बैठक



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और एकल विद्यालयों के विस्तार को लेकर सतपुड़ा भाग की संभाग स्तरीय बैठक डीपी चतुर्वेदी महाविद्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाग अध्यक्ष डॉ. के.के. चतुर्वेदी ने की। इसमें मध्यप्रदेश-राजस्थान के प्रभाग प्राथमिक शिक्षा प्रभारी मनोहर, संभाग उपाध्यक्ष मोहन, संभाग सचिव धनंजय सहित सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर अंचल के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में एकल विद्यालयों के विस्तार, समितियों के गठन और आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि एकल अभियान का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना है, जहां शासकीय विद्यालयों की पहुंच सीमित है। इन विद्यालयों के संचालन में समाज के सहयोग और गठित समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

जनसहयोग से आगे बढ़ेंगे एकल विद्यालय

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. के.के. चतुर्वेदी ने कहा कि एकल विद्यालयों के संचालन और विस्तार के लिए जनसहयोग आवश्यक है। समाज के संपन्न वर्ग, सहयोगी नागरिक और कार्यकर्ता मिलकर इन विद्यालयों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने संगठन के विस्तार के साथ अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में प्रत्येक अंचल में 56 सदस्यीय समितियों के गठन तथा संगठन को ग्राम से लेकर शहर, नगर, जिला, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। समिति विस्तार का कार्य नवरात्र तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

पांच जिलों के पदाधिकारियों ने रखे अनुभव

बैठक में सतपुड़ा एवं महाकौशल क्षेत्र के विभिन्न अंचलों से आए पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्रों की गतिविधियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर से आए प्रतिनिधियों ने एकल विद्यालयों के विस्तार को लेकर अपने सुझाव भी रखे। कार्यक्रम में भाग उपाध्यक्ष राजेंद्र बघेल, भाग सचिव चंद्रशेखर, उपाध्यक्ष प्रभा, संभाग समिति सदस्य शंकर दहिया, युवा इकाई से राकेश नागफासे, सिवनी अंचल अध्यक्ष कुंज बिहारी सनोदिया, गौरव दुबे, राजुल चौधड़िया, रिचा नेमा, वेद प्रकाश चौरसिया, शिवराम वर्मा, दिलीप शिवपाल, वीरेंद्र बिलगईयां, राजकुमार, सूरज पटेल, पुन्नू लाल परते, प्रकाश साकरे, मनोज, डॉ. देवी, दिलीप, रतन, आर.के. रघुवंशी, गजेश ठाकरे, संजय जैन, सरमन गौर एवं देवी सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सिवनी में दो बाइक की भिड़ंत, 2 घायल

सिवनी। सिवनी जिले के घंसौर थाना क्षेत्र में शनिवार रात सड़क हादसे में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना दारोट नाला के पास हुई। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा और मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार, शनिवार रात दारोट नाला के समीप दो मोटरसाइकिलें आमने-सामने आ गईं। इसी दौरान दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर अतिथियों ने अंत्योदय एवं सामाजिक सहभागिता का दिया संदेश

केवलारी। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के निदेर्शानुसार शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, केवलारी में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम मैं अध्ययन-सह-प्रशिक्षण कक्षा के संचालन के पश्चात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अशोक बन्देवार, जिला मीडिया सह प्रभारी, भाजपा जिला सिवनी, विशिष्ट अतिथि श्री अभिषेक तिवारी, अध्यक्ष, नवांकुर संस्था-न्यू प्रगतिशील समिति, विशिष्ट अतिथि श्री बोधराम साहू, अध्यक्ष, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति तथा जन अभियान परिषद के विकासखण्ड समन्वयक श्री अशोक बेन्द्रे की गरिमामयी उपस्थिति रही।

अंत्योदय को जनसेवा से जोड़ने का संदेश- कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए कार्यक्रम समन्वयक एवं जन अभियान परिषद के विकासखण्ड समन्वयक श्री अशोक बेन्द्रे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उद्देश्य एवं उनके विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी का चिंतन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। अंत्योदय की भावना को सामाजिक सहभागिता के माध्यम से धरातल पर उतारना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ समाज के बीच जाकर सामाजिक समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि श्री अशोक बन्देवार ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन सादगी, राष्ट्रसेवा और संगठन के प्रति समर्पण का प्रेरणास्रोत है। उनके एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार आज भी समाज और राष्ट्र के विकास के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और सकारात्मक योगदान देना भी है। विशिष्ट अतिथि श्री अभिषेक तिवारी ने कहा कि समाज के विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि युवा सामाजिक समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए आगे आएं, तो जनभागीदारी के माध्यम से गांव और समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से सेवा एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि श्री बोधराम साहू ने ग्रामीण विकास एवं जनसहभागिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांव के विकास में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया से जोड़ना ही वास्तविक सामाजिक विकास की दिशा है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार को जनसेवा और ग्राम विकास से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों एवं अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन, विचारों एवं सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम परामर्शदाता बालकराम डहेरिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में परामर्शदाता राधेश्याम बन्देवार, रामकृष्ण डहेरिया एवं कलावती ठाकुर का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में श्री मोतीराम हरदुआ द्वारा सभी अतिथियों, विद्यार्थियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के विद्यार्थी, परामर्शदाता एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।



नेता और अधिकारी क्या करेंगे लोकपथ एप में शिकायत या हर बार की तरह माला पहनकर आगे निकल जाएंगे?

सेवा यात्रा का स्वागत कर रखें बड़े-बड़े गड्ढे!



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- सेवा संकल्प अभियान के तहत निकलने वाली ह्यसेवा यात्राह्न 27 एवं 28 सितंबर को सिवनी जनपद क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से होकर गुजरने वाली है। यात्रा के स्वागत के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को फूलमाला, पेयजल, माइक, बैठक सहित तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन यात्रा के स्वागत से पहले सिवनी-छिंदवाड़ा मार्ग की बदहाल तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि यात्रा निकलने से पहले कुछ गड्ढों को भरने के नाम पर सड़क किनारे फुटपाथ में लगाई जाने वाली सीमेंट की ब्रिक्स डालकर पाटा गया है, जबकि कई स्थानों पर मिट्टी भरकर गड्ढों को समतल करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि यह स्थायी मरम्मत है या केवल यात्रा के गुजरने तक सड़क को ठीक दिखाने की कवायद?

यात्रा निकलते ही फिर दिखने लगेंगे गड्ढे?

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि गड्ढों में मिट्टी या अन्य अस्थायी सामग्री डालकर उन्हें भरा गया है तो बारिश और वाहनों की आवाजाही के बाद इनके फिर उभरने की आशंका है। वहीं फुटपाथ में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट की ब्रिक्स से गड्ढे भरना भी सड़क की स्थायी मरम्मत का विकल्प नहीं माना जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यात्रा के लिए सड़क को केवल ऊपर-ऊपर से ठीक किया जा रहा है, या वास्तव में सड़क की मजबूती और स्थायी मरम्मत पर ध्यान दिया जा रहा है?

रोड की बदहाली पहले भी रही सुर्खियों में- सिवनी-छिंदवाड़ा मार्ग की बदहाल स्थिति कोई पहली बार सामने नहीं आई है। यह मार्ग गड्ढों, सड़क की उखड़ी परत और मरम्मत की जरूरत को लेकर समय-समय पर सुर्खियों में रहा है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा सड़क के गड्ढों की फोटो लोकपथ एप पर भेजकर शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि जब यात्रा के साथ अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसी मार्ग से गुजरेंगे, तो क्या उन्हें सड़क के ये गड्ढे नजर आएंगे और क्या वे स्वयं लोकपथ एप पर इनकी शिकायत दर्ज कराएंगे? या फिर फूलमाला पहनकर स्वागत स्वीकार किया जाएगा और सड़क के गड्ढे पीछे छूट जाएंगे? यात्रा अभी गुजरी नहीं है, सड़क की बदहाली सामने है और कुछ स्थानों पर अस्थायी तौर पर गड्ढे भरे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि यात्रा के बाद भी यह सड़क इसी तरह दुरुस्त रहती है या फिर कुछ दिनों बाद गड्ढे एक बार फिर अपनी पुरानी जगह पर नजर आने लगते हैं।

महामाया मंदिर से दानपेटी चोरी, 3 आरोपी गिरफ्तार

सिवनी। सिवनी जिले के बरघाट नगर के महामाया मंदिर परिसर से दानपेटी चोरी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को शनिवार रात गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गई भगवा रंग की दानपेटी, उसमें से चोरी की गई नकदी और वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा स्कूटी जब्त की है। बरघाट थाना प्रभारी मोहनीश बेस ने बताया कि महामाया मंदिर परिसर वार्ड नंबर-3 निवासी नेमीचंद सूर्यवंशी ने 24 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 23 और 24 सितंबर की दरम्यानी रात अज्ञात चोर मंदिर की स्टील ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और दानपेटी चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 548/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (इठर) की धारा 305() और 331(4) के तहत जांच शुरू की गई। मंदिर में चोरी की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों और आने-जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई। ग्रामवासियों से मिली जानकारी, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र को जांच से जोड़ा गया। इसके बाद पुलिस टीम संदिग्धों तक पहुंची और तीन लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने मंदिर से दानपेटी चोरी करने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश काले उर्फ कालिया (29) निवासी नागपुर, अजय वरकड़े (29) निवासी ग्राम उलट, हाल नागपुर और सुधाकर बट्टी (28) निवासी ग्राम चिरचिरा, बरघाट शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकाल लोक से पीएम ई-बस सेवा एवं उज्जैन दर्शन सेवा का किया शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को प्रदेश में सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को गति देते हुए महाकाल लोक के अन्नक्षेत्र पार्किंग परिसर में पीएम ई-बस सेवा तथा उज्जैन दर्शन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शक्ति पथ, महाकाल लोक से बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने राजाराम रिसोर्ट तक यात्रा भी की। इस अवसर पर वेदपाठी बटुकों के द्वारा वेद मंत्रों का वाचन किया गया और डमरू वादन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कहा कि मैं भगवान महाकालेश्वर को प्रणाम करता हूं। आज उनकी नगरी में एक अद्भुत अलग प्रकार का दिन है। एक के बाद एक शहर को रोज एक नई सौगात मिल रही है । रोज नए प्रकार के विकास के कीर्तिमान बन रहे हैं। 21 साल पहले राज्य परिवहन निगम की बसें चला करती थीं, फिर किसी कारण से सार्वजनिक परिवहन बसों को बंद करना पड़ा। हमने वह अभाव आज पूरा किया है। राज्य परिवहन निगम की बसें एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगी। शहर के अंदर नगरीय स्तर पर भी बसें चलाई जाएंगी । उज्जैन में धार्मिक पर्यटन केंद्र के लिए 10 बसों की सौगात मिल रही है। हम सब इसमें यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा प्रदेशवासियों का सफर सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एवं ई-बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। उज्जैन में यह सेवा श्रद्धालुओं, पर्यटकों और नगरवासियों को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, डॉ लता वानखेड़े, महापौर मुकेश टटवाल, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण समिति के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, विवेक जोशी, राजेंद्र भारती, जगदीश पांचाल, प्रभुलाल जाटवा, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, संभागायुक्त आशीष सिंह,कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्रेयांस कूमट, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, सीईओ स्मार्ट सिटी संदीप सोनी, अधीक्षण यंत्री के ही मालवीय एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।



उज्जैन दर्शन मार्ग

उज्जैन दर्शन सेवा का निर्धारित मार्ग मेघदूत वन पार्किंग से प्रारंभ होकर महाकाल लोक, हरसिद्धि मंदिर, क्षिप्रा नदी, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, भर्तृहरि गुफा, गढ़ कालिका माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, सिद्धवट मंदिर, अंगारेश्वर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनि आश्रम, भूखी माता मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, अष्ट विनायक मंदिर, शनि नवग्रह मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बस स्टैंड एवं उज्जैन रेलवे स्टेशन होते हुए पुनः मेघदूत वन पार्किंग पर समाप्त होगा। इसका शुल्क 200 रुपये मात्र होगा। यात्री यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। यह बसें पूर्ण रूप से जीरो एमिशन रहेंगी , इनसे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा और यह इलेक्ट्रिकल चार्ज होंगी। यह मार्ग उज्जैन के प्रमुख मंदिरों एवं पौराणिक स्थलों को एक श्रृंखला में जोड़ेगा। उज्जैन दर्शन रूट की कुल लंबाई 27.01 किलोमीटर है।

बस संचालन की व्यवस्था

यात्री निर्धारित स्टॉप पर बस से उतरकर संबंधित मंदिर या दर्शनीय स्थल का दर्शन कर सकेंगे तथा दर्शन पूर्ण होने के बाद उसी स्टॉप से अगली उपलब्ध उज्जैन दर्शन बस में यात्रा जारी रख सकेंगे। निर्धारित वैधता अवधि के दौरान एक ही टिकट पर यात्री मार्ग के विभिन्न स्टॉप से बस में चढ़ और उतर सकेंगे। सभी प्रमुख मंदिरों एवं दर्शनीय स्थलों के निकट निर्धारित बस स्टॉप बनाए जाएंगे। यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए बसों का संचालन नियमित अंतराल पर किया जाएगा। प्रत्येक प्रमुख स्थल पर दर्शन एवं भ्रमण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहेगा। यह सेवा मेघदूत वन पार्किंग से प्रारंभ होकर प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को एक ही सेवा से प्रमुख दर्शन स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

आधुनिक सुविधाएं

बसों में लाइव सीसीटीवी, जीपीएस आधारित लाइव ट्रैकिंग, डिजिटल टिकटिंग तथा यूपीआई/डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बस में डिजिटल असिस्टेंट सह उज्जैन दर्शन गाइड भी उपलब्ध रहेंगे, जो प्रमुख मंदिरों, दर्शनीय स्थलों, मार्ग एवं दर्शन संबंधी आवश्यक जानकारी देंगे।

प्रमुख दर्शन स्थल एवं मान्यता

महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक एवं उज्जैन का अधिष्ठाता देव स्थल है। यहाँ की भस्म आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाकाल लोक शिव पुराण की कथाओं एवं शिव-स्वरूपों को मूर्तियों, स्तंभों और भित्तिचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। हरसिद्धि माता उज्जैन की प्राचीन शक्तिस्थली हैं। क्षिप्रा नदी के पवित्र घाटों पर स्नान एवं पूजा-अर्चना की मान्यता है। ऋणमुक्तेश्वर महादेव में पूजा से विभिन्न ऋणों से मुक्ति की मान्यता जुड़ी है। भर्तृहरि गुफाएँ राजा भर्तृहरि की तपस्या एवं नाथ संप्रदाय की साधना परंपरा से जुड़ी हैं। गढ़ कालिका मंदिर की मान्यता महाकवि कालिदास से जुड़ी हुई है। काल भैरव उज्जैन के रक्षक देवता माने जाते हैं। सिद्धवट पितृ कर्मों के लिए विशेष तीर्थ है। अंगारेश्वर एवं मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह संबंधी मान्यताओं से जुड़े हैं। सांदीपनि आश्रम वह स्थल है जहाँ मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण, बलराम एवं सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। भूखी माता, चिंतामण गणेश, अष्ट विनायक, शनि नवग्रह एवं इस्कॉन मंदिर भी इस मार्ग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

नगर की अन्य बस मार्ग व्यवस्था

उज्जैन शहर में सुगम परिवहन के अंतर्गत कुल 12 मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिनमें तपोभूमि से पानबिहार, उज्जैन रेलवे स्टेशन से कालियादेह महल, कानीपुरा से अभिलाषा कॉलोनी, देवास गेट से तपोभूमि, देवास गेट से ताजपुर, देवास गेट से नए आरटीओ कार्यालय, महाकाल चौराहा से अभिलाषा कॉलोनी, देवास गेट से नानाखेड़ा, अवंतिका विश्वविद्यालय से नानाखेड़ा, देवास गेट से मुरलीपुरा, तपोभूमि से नजरपुर तथा उज्जैन दर्शन मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों से नगर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक क्षेत्रों को बस सेवा से जोड़ा गया है। यह सेवा श्रद्धालुओं को महंगे निजी परिवहन पर निर्भरता घटाते हुए सुविधाजनक, किफायती और सुरक्षित दर्शन यात्रा उपलब्ध कराएगी। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के दृष्टिगत उज्जैन में सुगम आवागमन की यह व्यवस्था नगरवासियों एवं देश-विदेश से आने वाले भक्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

सिंहस्थ के लिए मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक मकान पर खुद चलाई गेती



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन के अब्दालपुरा स्थित अपने पैतृक मकान पर खुद गेती चलाकर सिंहस्थ 2028 के लिए प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य की शुरूआत की। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे अब्दालपुरा पहुंचे और विधिवत पूजा-अर्चना के बाद अपने मकान को सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाने की प्रक्रिया शुरू की। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सड़क और अन्य सुविधाओं के विस्तार का काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन के आधिकारिक पोर्टल पर भी सिंहस्थ से जुड़ी आधारभूत संरचना और उज्जैन के विकास को प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी उपलब्ध है। अब्दालपुरा उज्जैन की पुरानी बस्तियों में शामिल है। यहां एक ओर खजूर वाली मस्जिद और दूसरी ओर जीवाजीगंज थाना स्थित है। इनके बीच करीब 272 मकान बताए गए हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम और बोहरा समुदाय के परिवार रहते हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए यहां रहने वाले लोग अपने-अपने मकानों का हिस्सा हटाने के लिए तैयार हुए हैं। इस दौरान क्षेत्र में विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की सहभागिता भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पैतृक मकान का सड़क चौड़ीकरण की जद में आना इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से चर्चा का विषय रहा। मुख्यमंत्री ने स्वयं मकान पर गेती चलाकर उसे हटाने की शुरूआत की। सड़क चौड़ीकरण के लिए अपने मकान को हटाने के इस कदम को उन्होंने सिंहस्थ की तैयारियों और उज्जैन के विकास में व्यक्तिगत सहभागिता के रूप में सामने रखा। अब्दालपुरा निवासी कादर भाई ने कहा कि सड़क चौड़ी होने से क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या दूर होगी। उनका कहना है कि पहले सड़क संकरी होने के कारण वाहनों के आवागमन में परेशानी होती थी, लेकिन चौड़ीकरण के बाद लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मकानों की चौड़ाई भले ही अलग-अलग हो, लेकिन विकास के लिए सभी की सहभागिता दिखाई दे रही है और लोग सड़क चौड़ीकरण के लिए जगह देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री के पैतृक मकान के पड़ोसी पवन पांचाल ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा। सड़क के दूसरी ओर मुख्यमंत्री की बहन और नगर निगम उज्जैन की सभापति श्रीमती कलावती यादव का मकान भी चौड़ीकरण की जद में आ रहा है। दूध की दुकान चलाने वाले नरेंद्र जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के मकान भी चौड़ीकरण की जद में आने से यह संदेश जाता है कि सिंहस्थ की तैयारियों में सभी लोग सहभागी हैं। पूर्व पार्षद जगदीश पांचाल ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से उज्जैन के विकास को गति मिलेगी और सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन को सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के लोगों के अनुसार सड़क चौड़ी होने से स्थानीय व्यापार और आवागमन दोनों को लाभ मिल सकता है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत विभिन्न विकास और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन के लोगों ने विकास कार्यों में सहभागी बनकर स्वयं अपने मकान हटाने में सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन की आबादी करीब आठ लाख है, जबकि सिंहस्थ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सिंहस्थ के लिए अपने मकान और पूजा स्थलों को पीछे करने में सहयोग दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन के रहवासी स्वेच्छा से अपने पुश्तैनी घरों को हटाकर सड़क चौड़ीकरण में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय मैराथन में भी सहभागिता की और प्रतिभागियों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने नागरिकों से नियमित योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। पितृपक्ष के अवसर पर उन्होंने लोगों से अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि आचरण और कार्यों के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन से सीख लेने की बात कही।

अवंतिका का वैभव ही सदियों से रहा है इसका गौरव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के समान विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उज्जैन यानी अवंतिका एक प्राचीन नगर है और यहां का व्यापार, व्यवसाय तथा वैभव सदियों से इस नगर की पहचान और गौरव रहा है। उज्जैनवासियों ने हर काल में शहर के विकास में सहयोग किया है और आज भी लोग विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए स्वैच्छिक योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रविवार को महाकाल महालोक में विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 173 करोड़ रुपये की लागत के 15 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन को जल्द ही मेट्रो रेल की सौगात मिलेगी। उन्होंने बताया कि भोपाल के मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। ग्वालियर को नए महानगरीय शहर के रूप में विकसित करने के साथ ही दूरसंचार नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर से भोपाल और जबलपुर तक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सेवा भाव के साथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रही है। सुगम परिवहन सेवा के तहत नई परिवहन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। यात्री बसें एक नगर से दूसरे नगर के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य तक भी जाएंगी। उज्जैन में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उज्जैन दर्शन के लिए 10 नई प्रधानमंत्री ई-बस सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवहन सेवाओं से शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उज्जैन के विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों को सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम को उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य बालयोगी उमेशनाथ महाराज, सांसद डॉ. लता वानखेड़े और महापौर मुकेश टटवाल ने भी संबोधित किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उज्जैन का चौतरफा विकास हो रहा है और सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए शहर को सजाने-संवारने के कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष ओम जैन, सिंहस्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेन्द्रध भारती, संजय अग्रवाल, जगदीश पांचाल सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत मुख्यमंत्री डॉ. यादव और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर की। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में 15 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें 12 कार्यों का भूमिपूजन और तीन कार्यों का लोकार्पण शामिल है। भूमिपूजन किए गए कार्यों में नगर निगम उज्जैन के आठ बड़े कार्य शामिल हैं। इनमें गौशाला मार्ग से शिप्रा विहार मार्ग निर्माण, महाकाल लोक क्षेत्र में पार्किंग सुविधा, श्री महाकाल मंदिर परिसर का विकास और क्षिप्रा नदी के घाटों का जीर्णोद्धार प्रमुख हैं। इन कार्यों की कुल लागत 153.31 करोड़ रुपये है। इसके अलावा उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल मंदिर के पीछे भू-दृश्य विकास, पुलिस विभाग द्वारा चिंतामण जवासिया में पुलिस आवास और उन्हेल में थाना भवन तथा पर्यटन विभाग द्वारा 45 नगरीय वनों के विकास कार्य भी भूमिपूजन में शामिल हैं। वहीं लोकार्पित कार्यों में पुलिस आवास अधोसंरचना विकास निगम द्वारा नीलगंगा और उन्हेल में निर्मित पुलिस आवास एवं थाना भवन तथा ऊर्जा विभाग द्वारा बड़नगर में निर्मित 33/11 केवी उपकेंद्र शामिल हैं। इन तीनों लोकार्पित कार्यों की कुल लागत 19.56 करोड़ रुपये है। इन विकास कार्यों से उज्जैन के नागरिकों को अधोसंरचना, सुरक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

बीजों की कोठरी में सहेजी है पीढ़ियों की खुशहाली, बची हुई है देसी अनाज की विरासत

भोपाल, एजेंसी। शहडोल जिले के मझगवां गांव के सलैया टोला में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए अनाज केवल भोजन नहीं, बल्कि उनकी पहचान, परंपरा और खुशहाली का आधार है। घरों की कोठरियों में सुरक्षित रखे छोटे-छोटे बीज उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। इन्हीं बीजों से खेतों में फसल तैयार होती है, घर में अनाज पहुंचता है और परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। आधुनिक और संकर किस्मों के बढ़ते चलन के बीच यहां के बैगा और भूमिया समाज के किसान आज भी अपनी पुरानी देसी किस्मों को सहेजकर रखे हुए हैं। मझगवां के खेतों में झोलार, बांसपोर, ठर्री, सरैय्या, गुरमटिया, करन फूल और भेजरी जैसी पारंपरिक धान की किस्में आज भी उगाई जाती हैं। इसके साथ ही लेदरी कोदो, बासिन कोदो, कोदैली कोदो, बेमेरहा कुटकी, जाली कुटकी, छोटाही कुटकी, भदैली कुटकी, कागुन, समा और मिलो जैसे मोटे अनाज भी यहां की खेती और भोजन का हिस्सा हैं। अलग-अलग किस्मों के इन अनाजों को सुरक्षित रखना यहां के किसानों की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। मझगवां के किसान भोल्ली सिंह ने अपने खेतों में कई पारंपरिक फसलों को बचाकर रखा है। उनके खेत में झोलार धान, बांसपोर, सरैय्या, गुरमटिया, करन फूल और भेजरी जैसी देसी धान की किस्में उगती हैं। इसके अलावा कोदो, मक्का, मिलो, कागुन, कुटकी, लेदरी कोदो और बासिन कोदो की भी खेती की जाती है। उनके लिए इन फसलों की खुशी केवल अच्छी पैदावार तक सीमित नहीं है। खेत से अनाज घर आने और परिवार के भोजन में शामिल होने पर उन्हें अपनी मेहनत सफल होने का एहसास होता है। भोल्ली सिंह बताते हैं कि मोटा अनाज उनके रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है। वे पारंपरिक भोजन को अपनी तंदुरुस्ती से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र होने के बावजूद वे 20 से 25 किलोमीटर तक साइकिल चला लेते हैं। उनके लिए खेत में सुरक्षित रखे बीज केवल अगली फसल की तैयारी नहीं, बल्कि परिवार की परंपरा और जीवनशैली का हिस्सा हैं। मझगवां के सलैया टोला की बिरमतिया बैगा ने भी अपने खेतों में पारंपरिक अनाज और धान की कई किस्मों को सुरक्षित रखा है। उनके खेत में समा, कुटकी, सिकिया, काकुन, सरैय्या और ठर्री धान जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अलग-अलग मौसम में इन फसलों की खेती करना और उनसे प्राप्त अनाज को सुरक्षित रखना उनके परिवार की पुरानी परंपरा है।

अमित शाह के प्रस्तावित मध्यप्रदेश दौरे को लेकर डीजीपी ने तैयारियों की समीक्षा की

भोपाल, एजेंसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित मध्यप्रदेश दौरे के दौरान पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की जानी है। इसकी तैयारियों को लेकर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने रविवार को पुलिस मुख्यालय भोपाल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार साइबर अपराध, आपराधिक न्याय प्रणाली, कानून-व्यवस्था, आतंकवाद प्रतिरोध, नक्सल उन्मूलन, विदेशियों से जुड़े विषय, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण और पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा समन्वय सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक ने बैठक में सुरक्षित क्लिक, नशे से दूरी है जरूरी, नक्सलवाद के उन्मूलन और हार्टफुलनेस सहित मध्यप्रदेश पुलिस की विभिन्न पहलों और अभियानों पर भी चर्चा की। उन्होंने पुलिसिंग के अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों, आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा जनहित से जुड़े अभियानों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में इन अभियानों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के साथ पुलिस और नागरिकों के बीच जागरूकता एवं सहभागिता को भी प्रदर्शित किया जाए। बैठक में ई-शून्य प्राथमिकी, 1930 साइबर सहायता केंद्र, साइबर कमांडो प्रशिक्षण और सुरक्षित क्लिक जागरूकता अभियान की प्रगति की जानकारी दी गई। बताया गया कि सुरक्षित क्लिक अभियान के माध्यम से 8.6 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई गई है। आतंकवाद प्रतिरोध के अंतर्गत आतंकवाद निरोधक दस्ते की क्षमताओं और परिचालन दक्षता के साथ अंतरराज्यीय प्रकृति के मामलों में समन्वय पर भी चर्चा हुई। विदेशियों एवं अवैध प्रवासियों के विरुद्ध कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण और पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा समन्वय की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रणाली, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई-समन, चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण और शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था पर प्रस्तुतिकरण दिया। अभियोजन



निदेशालय, नेटग्रिड के उपयोग, नवीन न्याय संहिता के तहत दो वर्षों की तुलनात्मक स्थिति और फॉरेंसिक सेवाओं की जानकारी भी साझा की गई। बैठक में 57 मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। जेल विभाग ने आदर्श जेल अधिनियम-2023 के तहत मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी अधिनियम-2024 तथा आदर्श जेल नियमावली-2016 से संबंधित जानकारी बैठक में साझा की। पुलिस महानिदेशक ने आधुनिक तकनीक और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने पुलिसिंग से जुड़े सभी क्षेत्रों की जानकारी को प्रदर्शनी में सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव ने तीन अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में अपराध होने से लेकर नागरिक को न्याय मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें पुलिस, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, अभियोजन, जेल और अन्य संबंधित विभागों की भूमिका के साथ आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल व्यवस्थाओं को विभिन्न कक्षों, वीडियो, डिजिटल पर्दों, पोस्टरों और प्रतिरूपों के माध्यम से दशार्या जाएगा। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश पुलिस की साइबर जागरूकता, नक्सल उन्मूलन, सुरक्षित क्लिक, नशे से दूरी है जरूरी सहित विभिन्न जनहितकारी पहलों और उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के 520 विद्यार्थी तीन दिवसीय अहमदाबाद शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना

भोपाल, एजेंसी। प्रदेश के शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को कक्षा-कक्ष की पढ़ाई के साथ प्रत्यक्ष अनुभवों से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग ने अहमदाबाद शैक्षणिक भ्रमण की पहल की है। गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस भ्रमण में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 520 विद्यार्थी, 104 शिक्षक और स्कूल शिक्षा विभाग के छह नियंत्रण अधिकारी शामिल हैं। रविवार को 630 सदस्यीय दल भोपाल से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल से स्कूल शिक्षा विभाग की अपर परियोजना संचालक नंदा भिलावे कुशरे ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र बोरबन भी उपस्थित रहे। तीन दिवसीय इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े विषयों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से समझने का अवसर मिलेगा। यह भ्रमण शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। इस ओलंपियाड में प्रदेश के लगभग 65 हजार विद्यार्थियों ने सहभागिता की थी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से नई जानकारियों और अनुभवों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अहमदाबाद प्रवास के दौरान विद्यार्थी प्रमुख शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संस्थानों, विज्ञान केंद्र, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण करेंगे। इन स्थलों पर उन्हें वैज्ञानिक गतिविधियों, शैक्षणिक संस्थानों की कार्यप्रणाली और देश की विभिन्न उपलब्धियों को करीब से जानने और समझने का अवसर मिलेगा। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और नवाचार से जुड़े विषयों को केवल पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ाने के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर अनुभव आधारित शिक्षा से जोड़ना है।

किसानों का भूमि, फसल एवं रकबे का विवरण एग्रीस्टेक डाटाबेस से होगा सत्यापित

धान उपार्जन के लिए किसान पंजीयन जारी, 10 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। **खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। पंजीयन की प्रकिया 10 अक्टूबर तक चलेगी। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जिले में किसान पंजीयन के लिए कुल 51 पंजीयन केन्द्र निर्धारित किए हैं। पंजीयन कार्य सभी कार्य दिवसों में किया जाएगा। रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिन पंजीयन नहीं होगा। इस वर्ष किसान पंजीयन प्रक्रिया को एग्रीस्टेक डाटाबेस से जोड़ा गया है। पंजीयन के दौरान किसान के स्वामित्व वाले खसरे, रकबे तथा बोई गई फसल की जानकारी एग्रीस्टेक डाटाबेस से प्राप्त होगी। इससे पंजीयन में किसान की वास्तविक भूमि एवं फसल संबंधी जानकारी का सत्यापन किया जा सकेगा।**

विगत वर्ष के पंजीकृत और नवीन किसानों के लिए अलग विकल्प

पंजीयन केन्द्रों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए दो विकल्प उपलब्ध है। एक विकल्प विगत वर्ष पंजीकृत किसानों के लिए तथा दूसरा नवीन किसानों के पंजीयन के लिए होगा। पूर्व पंजीकृत किसान आधार नंबर, समग्र परिवार आईडी, मोबाइल नंबर, एग्रीस्टेक किसान आईडी अथवा विगत वर्ष की किसान पंजीयन आईडी दर्ज कर अपना विवरण प्राप्त कर सकेंगे। आवश्यकता होने पर विवरण में नियमानुसार संशोधन किया जा सकेगा। नवीन किसानों को आवेदन में अपना पूरा विवरण दर्ज करना होगा। पंजीयन के दौरान किसान का सही आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। आधार का बायोमैट्रिक अथवा ओटीपी सत्यापन होने के बाद यूआईडीएआई के आधार डाटाबेस में दर्ज किसान की जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी। किसान के नाम और विवरण का आधार डाटाबेस से मिलान होने पर ही पंजीयन सुरक्षित किया जा सकेगा।

भूमि एवं फसल का विवरण एग्रीस्टेक से लिया जाएगा

किसान पंजीयन में भूमि के खसरा नंबर, रकबा और बोई गई फसल की जानकारी एग्रीस्टेक डाटाबेस से ली जाएगी। पंजीयन में संबंधित किसान के खसरे की ही जानकारी दर्ज की जा सकेगी। यदि एग्रीस्टेक में किसान के सभी खसरे उपलब्ध नहीं हैं, तो शेष खसरे संबंधित पटवारी, सीएससी, ग्राम सहायक अथवा फार्मर रजिस्ट्री एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से एग्रीस्टेक डाटाबेस में जोड़े जा सकेंगे। खसरे में दर्ज फसल तथा उसके सिंचित अथवा असिंचित रकबे के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। किसान को आवेदन में खसरेवार बोई गई फसल का विवरण दर्ज कराना होगा। ई-उपार्जन पोर्टल को एग्रीस्टेक से एकीकृत किए जाने के कारण भू-स्वामी के स्वामित्व वाले खसरे, फसल एवं रकबे की जानकारी के साथ किसान का यूनिक कोड और एग्रीस्टेक फार्मर आईडी भी पंजीयन डाटा में दर्ज होगा।

आधार नहीं होने पर भी निर्धारित प्रक्रिया से पंजीयन की सुविधा

जिन किसानों के पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें आधार केन्द्र पर जाकर आधार के लिए आवेदन करना होगा। समग्र आईडी अथवा आधार आवेदन की पंजीयन पावती के आधार पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसान का पंजीयन किया जा सकेगा। किसान द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से सत्यापन के बाद पंजीयन सुरक्षित किया जाएगा। सफल पंजीयन के बाद इसकी जानकारी किसान को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। किसान पंजीयन की जानकारी का प्रिंट भी पोर्टल से प्राप्त कर सकेगा।

सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के लिए विशेष व्यवस्था

सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन सहकारी समितियों तथा सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर किया जाएगा। यदि सिकमी अथवा बटाईदार किसान ने एक से अधिक किसानों की भूमि सिकमी या बटाई पर ली है, तो प्रत्येक मूल किसान के साथ पृथक अनुबंध करना होगा और प्रत्येक के लिए अलग पंजीयन किया जाएगा। ऐसे किसानों को मूल किसान तथा स्वयं के आधार नंबर, एग्रीस्टेक किसान आईडी और निर्धारित प्रारूप में सिकमी/बटाई अनुबंध की प्रति पंजीयन केन्द्र पर प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध की स्पष्ट स्कैन प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होगी। सिकमी/बटाईदार किसान के पंजीयन में मूल भू-स्वामी की एग्रीस्टेक किसान आईडी और आधार नंबर भी दर्ज किए जाएंगे तथा मूल भू-स्वामी का ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक के माध्यम से प्रमाणीकरण किया जाएगा। वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन में वन पट्टा क्रमांक, खसरा, रकबा एवं बोई गई फसल की जानकारी दर्ज की जाएगी। वनाधिकार पट्टाधारी किसानों का वन पट्टा तथा सिकमी/बटाईदार किसानों का सिकमी/बटाई अनुबंध 15 सितंबर 2026 से पूर्व की अवधि में निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। सिकमी/बटाई अनुबंध की अवधि अधिकतम पांच वर्ष निर्धारित है।

गलत खसरा जोड़ने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

किसान पंजीयन के दौरान बोई गई फसल, उसकी किस्म तथा विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी भी आवेदन में ली जाकर पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। किसी अन्य व्यक्ति के खसरे को किसान के पंजीयन में जोड़े जाने अथवा गलत पंजीयन किए जाने की स्थिति में संबंधित समिति प्रबंधक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध दंडात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



गौशाला में अनियमित्ताओं के चलते मवेशियों की मौत का आरोप

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। नगर निगम की अमीरगंज गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे हैं। रविवार को सामने आए एक वीडियो में गौ-सेवक एवं समाजसेवी ने गौशाला परिसर में मवेशियों के भूख, प्यास और इलाज के अभाव से दम तोड़ने की बात कही। उन्होंने गौशाला में चारे-पानी और इलाज की व्यवस्था को लेकर भी नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गौ-सेवक एवं समाजसेवी इंद्र मिश्रा के मुताबिक, गौशाला में बड़ी संख्या में गायों को पर्याप्त चारा-पानी और समय पर उपचार नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसर में देखरेख के लिए जिम्मेदार कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं रहते। प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। मामले में महापौर प्रीति सूरी ने बताया- हमने गौशाला के लिए कलेक्टर महोदय से 25 एकड़ जमीन मांगी है। फिलहाल अस्थाई रूप से आमीरगंज में व्यवस्था की गई है। यहां पर्याप्त चारे और भूसे का प्रबंध है। गायों की मृत्यु किन कारणों से हो रही है, इसकी जांच कराई जाएगी और आज हम स्वयं गौशाला का निरीक्षण करेंगे।

बारिश में रास्ते पर कीचड़ का दावा

अमीरगंज गौशाला नगर निगम सीमा के अंतिम छोर पर स्थित बताई गई है। मिश्रा का कहना है कि बारिश के दौरान गौशाला तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग पर कीचड़ हो जाता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। गौ-सेवकों और स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों से गौशाला में चारे-पानी की पर्याप्त व्यवस्था, पशुओं के उपचार की सुविधा और व्यवस्थाओं की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने जिम्मेदार पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।



हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, तुलसी और चिया बनीं नई उम्मीद, प्रतिष्ठित कंपनियों ने भी खरीद में दिखाई रुचि

पारंपरिक खेती से नवाचार की ओर बढ़े कदम, 450 किसानों ने रचा बदलाव का नया अध्याय



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। खेत वही हैं, किसान वही हैं, लेकिन अब खेती का अंदाज बदल रहा है। जिन खेतों में कभी परंपरागत फसलों की ही उम्मीद बोई जाती थी, वहां अब हल्दी की पीली रंगत, अदरक की खुशबू, अश्वगंधा की जड़ें, तुलसी की हरियाली और चिया के छोटे-छोटे बीज भविष्य की नई संभावनाओं का संदेश दे रहे हैं। ढीमरखेड़ा और बड़वारा क्षेत्र के 450 से अधिक आदिवासी किसानों ने करीब सवा सौ एकड़ में पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर प्राकृतिक, औषधीय और मसाला फसलों को अपनाया है। लगातार तीसरे वर्ष आगे बढ़ रही यह पहल अब खेतों में फसल बदलने से कहीं आगे निकलकर किसानों की सोच में बदलाव की कहानी बन गई है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा प्राकृतिक, औषधीय और बागवानी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को दिए गए निदेशों के बाद किसानों को नई फसलों से जोड़ने के गंभीर प्रयास किए गए। शुरूआत में नई फसल, नई तकनीक और बाजार को लेकर किसानों के मन में कई सवाल थे, लेकिन पर्यावरणविद् श्री निर्भय सिंह के सद्प्रयासों आदिवासी किसानों के मन से धीरे-धीरे तमाम आशंकाओं को भरोसे में बदल दिया।

एक खेत की सफलता बनी दूसरे खेत की उम्मीद

पर्यावरणविद् एवं मानव जीवन विकास समिति के सचिव श्री निर्भय सिंह बताते हैं कि पिछले वर्ष किसानों को अश्वगंधा के निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए गए थे। करीब 25 एकड़ में अश्वगंधा की खेती हुई। तैयार उपज नीमच कृषि उपज मंडी में 25 हजार रुपये में बेची गई और इसका सीधा लाभ उत्पादक किसानों को मिला। यह अनुभव किसानों के लिए एक तरह से रास्ता दिखाने वाला साबित हुआ। इस वर्ष नई फसलों का रकबा और किसानों की संख्या दोनों बढ़ी है। इस वर्ष 175 किसान हल्दी, 100-100 किसान अश्वगंधा और तुलसी तथा 75 आदिवासी किसान अदरक की खेती कर रहे हैं। वहीं 15 किसानों ने करीब आधा एकड़ में चिया की खेती की है। अनुमान के मुताबिक इन खेतों से करीब 700 से 800 क्विंटल अदरक, 2500 से 3000 क्विंटल हल्दी और लगभग 750 किलोग्राम तुलसी की उपज संभावित है। अश्वगंधा की भी इस वर्ष अच्छी उपज होने की उम्मीद है।

अब फसल खेत से बाजार तक पहुंचाने की तैयारी

नई खेती के साथ किसानों के सामने उपज के बेहतर बाजार की चुनौती भी रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एफपीओ संगमबीडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है। एफपीओ किसानों की उपज को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए नीमच कृषि उपज मंडी, डाबर इंडिया लिमिटेड और महाराष्ट्र बेस्ड सुहाना मसाला सहित अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों और बड़े औद्योगिक संस्थानों से लगातार बातचीत कर रहा है। इन कंपनियों ने जिले में उत्पादित फसलों को खरीदने में रुचि दिखाई है।

आठ गांवों से शुरू हुई राह, अब बड़वारा तक पहुंची

नाबार्ड के टीडीएफ फंड के अंतर्गत नानबाड़ी परियोजना के तहत ढीमरखेड़ा विकासखंड के कोठी, हर्राई, सगौना, सिवनी, दैगवां, दियागढ़, उमरपानी और छाहर , भलवारा, मेर, पहरुआ, कटारिया, खदंवारा, बांध, भमका, महगवां, सर्रा, तिलमन और बिजौरी गांवों के किसान मसाला एवं औषधीय फसलों की खेती से जुड़े हैं? इसके अलावा बड़वारा क्षेत्र के भदौरा, पथवारी, विलायतकलां, पठरा, भादावर, जमुनियां, बिजौरी, भमराड, चादन और चपहनी गांवों में भी किसान इन फसलों की खेती कर रहे हैं इन गांवों में अश्वगंधा, हल्दी, अदरक और तुलसी की खेती की जा रही है। राज्य शासन के कृषि विभाग की आत्मा, नाबार्ड के नानबाड़ी कार्यक्रम और मानव जीवन विकास समिति द्वारा किसानों को निःशुल्क बीज देकर इस पहल से जोड़ा गया है। श्री निर्भय सिंह बताते हैं कि शुरूआती दौर में किसानों के मन में नई फसलों को लेकर हिचक थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एक किसान की सफलता दूसरे किसान के लिए प्रेरणा बन रही है और एक खेत में आजमाया गया प्रयोग अगले खेत तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि ढीमरखेड़ा और बड़वारा में साल-दर-साल मसाला और औषधीय फसलों का रकबा बढ़ रहा है। इन खेतों में उग रही हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, तुलसी और चिया केवल फसलें नहीं हैं। ये उस बदलाव के प्रतीक हैं, जिसमें किसान अब केवल उपज पैदा करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य की संभावनाएं भी तलाश रहा है। खेतों में हो रहा यह बदलाव आने वाले समय में कटनी के इन ग्रामीण अंचलों की कृषि तस्वीर को एक नई दिशा मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस विशेषः दक्षिण पन्ना वन विभाग की पहल से 5 और बेटियों का प्रतिष्ठित अस्पतालों में प्लेसमेंट

पन्ना। अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर दक्षिण पन्ना वनमंडल की बेटियों की सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। हाल ही में कल्पना यादव, रोशनी यादव, रीशू यादव, सीता कुमारी और ज्योति चौधरी का भोपाल के अपोलो सेज अस्पताल में चयन हुआ है, जहां उन्हें लगभग ?15,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इन पांच बेटियों की सफलता के साथ दक्षिण पन्ना वनमंडल की पहल से प्रतिष्ठित अस्पतालों में रोजगार पाने वाली बेटियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इनकी उपलब्धियां दशार्ती हैं कि पन्ना के असली हीरे केवल यहां की धरती में ही नहीं, बल्कि यहां की बेटियों में भी हैं। मध्यप्रदेश वन विभाग के दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन (ऋ्नट) के अंतर्गत संचालित जनरल ड्यूटी असिस्टेंट (ऋ्नअ) प्रशिक्षण कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे पहले चार बेटियों को शाल्बी अस्पताल, जबलपुर तथा आठ को मेदांता अस्पताल, इंदौर में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए थे। इन सफल प्रशिक्षार्थियों में प्रतीक्षा दुबे, सरस्वती गड़ारी, शिवानी साहू एवं प्रतीक्षा गर्ग सहित अन्य बेटियां शामिल हैं। हाल ही में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भी इन बेटियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया था। शाहनगर वन परिक्षेत्र में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वॉकहार्ट फाउंडेशन को प्रशिक्षण सहयोगी संस्था बनाया गया था। कार्यक्रम का संचालन वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री राजुल कटारे एवं प्रशिक्षण पर्यवेक्षक श्री आशीष पाण्डेय, वनपाल, की देखरेख में किया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण एवं वनांचल की बेटियों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। दक्षिण पन्ना वनमंडल की यह पहल वन संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस पर इन 17 बेटियों की उपलब्धियां यह संदेश देती हैं कि उचित अवसर, कौशल प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन मिलने पर ग्रामीण अंचलों की बेटियां भी आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार, समाज और जिले का नाम रोशन कर सकती हैं।

पुलिस की तत्परता से बची जान

शाहनगर में युवक ने ब्लेड से घायल कर उठाया आत्मघाती कदम



शाहनगर। पन्ना-कटनी मार्ग स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास एक युवक द्वारा खुद को ब्लेड से घायल कर आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किए जाने से हड़कंप मच गया। युवक की पहचान राजेंद्र बर्मन उर्फ बेटा, पिता गंगाराम बर्मन, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी बिसानी, हाल निवास शाहनगर के रूप में बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही शाहनगर पुलिस मौके पर पहुंची। सहायक उप निरीक्षक रामकृष्ण पाण्डेय ने तत्परता दिखाते हुए युवक के हाथ से ब्लेड छुड़ाकर उसे काबू में लिया। इसके बाद पुलिस ने युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर पहुंचाया, जहां डॉ. आशीष तिवारी ने प्राथमिक उपचार किया। हालत को देखते हुए युवक को आगे के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय कटनी रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी रवि सिंह जादौन भी मौके पर पहुंचे और युवक के पिता से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी। फिलहाल युवक का उपचार जारी है। घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। उपरोक्त घटना की सूचना स्थानीय पत्रकार राजकमल पाण्डेय द्वारा दी गई

दो आरोपी गिरफ्तार, 2 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा एवं मोटरसाइकिल सहित कुल 86,000 का मशरूका जप्त

पन्ना पुलिस की कोतवाली थाना अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही



पन्ना,। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वंदना चौहान तथा समस्त एसडीओपी पन्ना के मार्गदर्शन में पन्ना पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना निरीक्षक रोहित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस को अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध गांजा का परिवहन एवं बिक्री करने की फिराक में खड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 26.09.2026 की रात्रि थाना कोतवाली पन्ना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति काले रंग की होंडा शाइन मोटरसाइकिल क्रमांक टढ 35 टउ 9945 पर एक बोरी में अवैध गांजा छिपाकर पट्टी तिराहा (लक्ष्मीपुर रोड) पर बिक्री करने की फिराक में खड़े हैं। सूचना की तस्दीक एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया।

नियमानुसार तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अवैध गांजा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को विधिवत जप्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के बताए अनुसार प्रकरण में फरार आरोपी शिवम यादव, निवासी ग्राम कल्याणपुर की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजे जाने की कार्यवाही की गई।

जप्त मशरूका-

अवैध गांजाः 2 किलो 120 ग्राम – अनुमानित कीमत ?36,000/- , मोटरसाइकिलः काले रंग की होंडा शाइन, क्रमांक टढ 35 टउ 9945 – अनुमानित कीमत 50,000/- - कुल जप्त मशरूकाः ?86,000/।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम 1. दशरथ यादव पिता मंगल सिंह यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम बिलखुरा, थाना कोतवाली पन्ना।

2. प्रमोद यादव पिता पान सिंह यादव, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम बिलखुरा, थाना कोतवाली पन्ना।

फरार आरोपी-* शिवम यादव, निवासी ग्राम कल्याणपुर।

सराहनीय योगदान* - उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित मिश्रा, उनि प्रज्ञा परोहा, प्रधान आरक्षक वृषकेतु रावत, आरक्षक संदीप तिवारी, राहुल सिंह, अमित द्विवेदी, प्रसंग मिश्रा, जीतेन्द्र पटेल, लक्ष्मीनारायण एवं चालक परमलाल का सराहनीय योगदान रहा।

ओम होम हैल्थ केयर सर्विस
हमारे पास अशक्त बुजुर्ग मरीजों की देखभाल हेतु नर्स,वार्ड वॉय,आया बाई,फिजियोथैरेपी और दवाईयॉ घर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्रो.जितेन्द्र पटैल CERVIC - 24X7 Hourse
मो. 9340721556,9753518166
पता-केनरा बैंक महाराष्ट्र हॉई स्कूल गोल बाजार जबलपुर(म.प्र.)

Manufacturer of t-shirts & lowers Mo. 9174614421, 9406763810
CHANDRAKALA TEXTILES
सभी प्रकार की टी-शर्ट ऑर्डर पर बनाई और प्रिंट की जाती हैं और स्पोर्ट्स सबलिमेसन जर्सी बनाई जाती हैं।
Address : shop no 151, jabalpur fashion design cluster market Lema garden Gohalpur jabalpur 482001

पदस्थापना को लेकर नियमों पर उठे सवाल, किस आदेश के आधार पर मिली जिम्मेदारी? जनजातीय कार्य विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग

सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में ओबीसी शिक्षक को अधीक्षक का प्रभार!



दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। तहसील मुख्यालय घुघरी में संचालित सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में अधीक्षक के प्रभार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार छात्रावास की व्यवस्था की जिम्मेदारी वर्तमान में ओबीसी वर्ग के एक शिक्षक को दी गई है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि अधीक्षक का प्रभार किस विभागीय आदेश और किन नियमों के तहत सौंपा गया है। मामला किसी शिक्षक की व्यक्तिगत योग्यता या कार्यक्षमता का नहीं, बल्कि अधीक्षक के प्रभार की विभागीय प्रक्रिया और निर्धारित पात्रता का है। यदि शासन अथवा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा इस संबंध में कोई विशेष नियम, निर्देश या पात्रता निर्धारित की गई है, तो उसका पालन किया गया या नहीं, यह विभाग को स्पष्ट करना चाहिए।

छात्रावास आदिवासी विद्यार्थियों के लिए, व्यवस्था पर सवाल

सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की भोजन, आवास, सुरक्षा, अनुशासन, अध्ययन एवं दैनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अधीक्षक पर होती है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि विभागीय नियमों में अधीक्षक पद अथवा प्रभार के लिए किसी विशेष पात्रता या अन्य शर्त का उल्लेख है, तो संबंधित शिक्षक को जिम्मेदारी सौंपने से पहले विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया जाना चाहिए था।

किस आदेश के आधार पर मिली जिम्मेदारी?

मामले में अब विभाग से कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं– अधीक्षक का प्रभार किस आदेश के तहत दिया गया? आदेश किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया? संबंधित शिक्षक की अधीक्षक पद के लिए निर्धारित पात्रता क्या है? क्या शासन के नियमों में अधीक्षक पद के लिए वर्ग संबंधी कोई विशेष प्रावधान है? क्या प्रभार देने से पहले संबंधित नियमों और निदेर्शों का परीक्षण किया गया? - जिले के अन्य आदिवासी छात्रावासों में अधीक्षक पद पर नियुक्ति अथवा प्रभार देने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

नियमों की स्थिति स्पष्ट करे विभाग

मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल शिक्षक के ओबीसी वर्ग से होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनकी पदस्थापना नियम विरुद्ध है। वास्तविक स्थिति लागू शासनादेश, विभागीय नियम, पद की पात्रता और जारी किए गए प्रभार आदेश की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। इसीलिए जनजातीय कार्य विभाग से स्थानीय लोगों की संदेश की दृष्टि को साफ करने के लिए स्पष्ट करना जरूरी हे कि संबंधित आदेश और लागू नियमों की स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट की जाए, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।

छात्रावास व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी

आदिवासी विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों में अधीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में पदस्थापना एवं प्रभार की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमसम्मत होना जरूरी है। यदि प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और यदि प्रभार पूरी तरह नियमों के अनुरूप है तो विभाग को आदेश एवं नियम स्पष्ट कर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए।

जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि घुघरी के सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में अधीक्षक के प्रभार की विभागीय जांच कराई जाए। संबंधित आदेश, शिक्षक की पात्रता तथा लागू शासनादेशों का परीक्षण किया जाए। अब देखना यह है कि जनजातीय कार्य विभाग इस मामले में संबंधित आदेश और नियमों की स्थिति स्पष्ट करता है या फिर सवालों के बीच मामला यूं ही चलता रहता है।

इनका कहना हैं...

इस विषय पर अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन कल मैं ऑफिस जाकर दिखवा लेता हूं ।

डॉ अरुण शुक्ला, सहायक आयुक्त मंडला



जनजातीय कार्य विभाग के परिसर में निर्माण व्यवस्था पर उठे सवाल, मुख्य द्वार भी बना चर्चा का विषय; स्थल निरीक्षण और स्वीकृत प्राक्कलन की जांच की मांग

सड़क बनी, नाली भूले जिम्मेदार! बारिश में जलभराव से जूझ रहा सिझौरा का आवासीय परिसर

भुआ-बिछिया (सिझौरा)। भुआ-बिछिया विकासखंड के सिझौरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के आवासीय परिसर में कराए गए सड़क निर्माण के बाद अब जल निकासी की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। परिसर में सड़क तो बना दी गई, लेकिन बारिश के पानी की निकासी के लिए आवश्यक नालियों का निर्माण नहीं होने से बारिश के दौरान जगह-जगह पानी जमा होने की स्थिति सामने आ रही है। इससे परिसर में रहने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह सवाल खड़ा कर रही है कि जब सड़क निर्माण की योजना तैयार की गई तो जल निकासी जैसी बुनियादी आवश्यकता को आखिर किस स्तर पर नजरअंदाज किया गया। सड़क निर्माण के साथ नाली व्यवस्था का अभाव निर्माण की समग्र योजना, स्थल के आकलन और तकनीकी निरीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है।

सड़क की उपयोगिता पर भी सवाल

बारिश के दौरान परिसर में पानी जमा होने से सड़क निर्माण की उपयोगिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। यदि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो पानी सड़क और परिसर में जमा होकर निर्माण की गुणवत्ता एवं उसकी टिकाऊपन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में निर्माण कार्य के दौरान स्थल की वास्तविक परिस्थितियों का तकनीकी आकलन किया गया था या नहीं, इसकी जांच जरूरी हो गई है।

मुख्य द्वार भी चर्चा में

आवासीय परिसर का मुख्य द्वार भी स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान स्वरूप शैक्षणिक एवं आवासीय परिसर की अपेक्षा किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार जैसा नजर आता है। लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग से जुड़े परिसर की पहचान और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वार सहित परिसर की समग्र व्यवस्था को बेहतर बनाया जाना चाहिए।

प्राक्कलन और तकनीकी निरीक्षण की जांच जरूरी

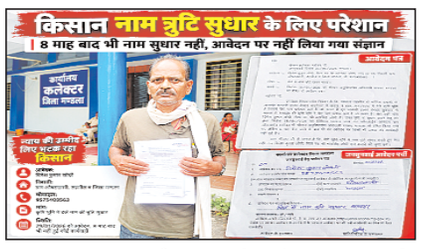
सड़क निर्माण में नाली व्यवस्था का प्रावधान था या नहीं, निर्माण किस स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर कराया गया, कार्य की तकनीकी निगरानी किस अधिकारी द्वारा की गई और निर्माण पूर्ण होने के बाद स्थल का निरीक्षण किया गया या नहीं—इन सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है।

प्रशासन करे स्थल निरीक्षण

मामला जनजातीय कार्य विभाग के आवासीय परिसर से जुड़ा होने के कारण अब जिला प्रशासन से स्थल का भौतिक निरीक्षण कराने की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके की वास्तविक स्थिति का आकलन कर स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी मापदंड, निर्माण कार्य और जल निकासी व्यवस्था की जांच कराई जानी चाहिए। यदि निर्माण में कोई कमी पाई जाती है तो उसे संबंधित एजेंसी से दूर कराया जाना चाहिए। सिझौरा के इस आवासीय परिसर की स्थिति ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या निर्माण कार्य केवल सड़क और ढांचा तैयार करने तक सीमित रह गया है, या परिसर में रहने वाले कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों और भविष्य की उपयोगिता को भी योजना में शामिल किया गया था? अब निगाह जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्रवाई पर है।

नाम की त्रुटि सुधार के लिए 8 माह से भटक रहा किसान, राजस्व रिकॉर्ड में दिनेश की जगह दर्ज धनेश्वर और धनौरा

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। किसानों की सुविधा के लिए राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन और समयबद्ध बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन मंडला तहसील से सामने आए एक मामले में किसान अपने नाम की त्रुटि सुधार के लिए पिछले करीब आठ माह से कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर बताया जा रहा है। मामला मंडला तहसील के सर्किल बम्हनी अंतर्गत पटवारी हल्का सेक्टर खड़देवरा और सुकतरा से जुड़ा है। ग्राम औघटखपरी निवासी कृषक दिनेश कुमार, पिता स्व. महासिंह लोधी का कहना है कि संबंधित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में उनके नाम के स्थान पर अलग-अलग नाम दर्ज हो गए हैं।



कहीं धनेश्वर, कहीं धनौरा दर्ज- किसान के अनुसार पटवारी हल्का सेक्टर खड़देवरा में खसरा नंबर 608 तथा 761/2(र) की कृषि भूमि में ह्यधनेश्वरह्ल नाम दर्ज है। वहीं सेक्टर सुकतरा में खसरा नंबर 174(र) की भूमि में ह्यधनौराह्ल नाम दर्ज बताया गया है। किसान का दावा है कि दोनों प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण हैं और सही नाम दिनेश कुमार दर्ज किया जाना है। **29 जनवरी को जमा किया था आवेदन-** पीड़ित किसान के अनुसार नाम त्रुटि सुधार के लिए नियमानुसार चालान राशि जमा कर ऑनलाइन आवेदन किया गया। इसके बाद आवेदन की मूल प्रति के साथ आधार कार्ड, अंकसूची, खसरा, बही, ग्राम पंचायत प्रमाण-पत्र और स्कूल के दाखिल-खारिज की छायाप्रतियां संलग्न कर 29 जनवरी 2026 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय, मंडला में ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया गया। **जनसुनवाई में भी लगाई गुहार-** किसान ने बताया कि आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने के बाद 30 जून 2026 को कलेक्टर जनसुनवाई में भी आवेदन दिया गया, लेकिन इसके बाद भी नाम सुधार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। **किसान की परेशानी-** किसान का कहना है कि करीब आठ माह बीत जाने के बाद भी उसे यह नहीं बताया गया कि आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, त्रुटि सुधार किस स्तर पर लंबित है और नाम कब तक सुधारा जाएगा।

समयबद्ध व्यवस्था के बावजूद देरी पर सवाल- आज अधिकांश राजस्व सेवाओं को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा चुका है और विभिन्न कार्यों के निराकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया भी है। ऐसे में नाम की एक त्रुटि सुधार के लिए किसान को महीनों इंतजार करना पड़े, तो व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। किसान का कहना है कि उसने आवश्यक दस्तावेज और आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा किए हैं। यदि आवेदन में कोई कमी है तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, और यदि दस्तावेज पूर्ण हैं तो प्रकरण का समय पर निराकरण होना चाहिए। **अब उठ रहे ये सवाल-** किसान के 29 जनवरी के आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? जनसुनवाई में दिए आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है? नाम त्रुटि सुधार किस अधिकारी या शाखा स्तर पर लंबित है? किसान को प्रकरण की स्थिति की जानकारी क्यों नहीं दी गई? **किसान को चाहिए सिर्फ रिकॉर्ड में अपना सही नाम-** यह मामला किसी बड़ी मांग का नहीं, बल्कि राजस्व अभिलेख में दर्ज नाम की त्रुटि सुधार का है। किसान की अपेक्षा है कि संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार प्रकरण का शीघ्र निराकरण करें और उसे कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। **तथ्य स्थिति-** समाचार किसान द्वारा बताए गए आवेदन, दस्तावेजों और राजस्व अभिलेख में नाम संबंधी कथित त्रुटि पर आधारित है। संबंधित राजस्व अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

नगर परिषद में ऑनलाइन कामकाज की निष्पक्ष जांच की मांग, योग्यता और कार्यक्षमता की समीक्षा पर उठे सवाल

कंप्यूटर ऑपरेटर की तकनीकी दक्षता पर सवाल, जवाब देने से अधिकारी क्यों बच रहे?

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। नगर परिषद भुआ-बिछिया में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की तकनीकी दक्षता और ऑनलाइन कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि संबंधित कर्मचारी की योग्यता और कार्यक्षमता को लेकर शिकायतें या आपत्तियां सामने आ रही हैं, तो उनकी वास्तविकता का पता निष्पक्ष तकनीकी परीक्षण और संबंधित अभिलेखों की जांच से लगाया जा सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब नगर परिषद का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन और डिजिटल व्यवस्था से जुड़ चुका है, तब तकनीकी जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारी की वास्तविक दक्षता की जांच कराने में परेशानी क्या है? जांच से कर्मचारी की योग्यता भी स्पष्ट होगी और उसके खिलाफ उठ रहे सवालों की वास्तविकता भी सामने आ सकेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

संबंधित कर्मचारी की तकनीकी दक्षता को लेकर उठ रही आपत्तियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय अभिलेखों और तकनीकी परीक्षण के आधार पर स्थिति स्पष्ट किया जाना जरूरी है।

कंप्यूटर संचालन और ऑनलाइन कार्यों पर उठ रही आपत्तियां

स्थानीय स्तर पर सामने आई चर्चाओं के अनुसार संबंधित कर्मचारी के कंप्यूटर संचालन, ऑनलाइन प्रविष्टियों और तकनीकी कार्यों को लेकर आपत्तियां उठाई जा



रही हैं। इन आपत्तियों की सत्यता स्थापित करने के लिए किसी स्वतंत्र और सक्षम तकनीकी अधिकारी या विशेषज्ञ से परीक्षण कराया जाना एक पारदर्शी विकल्प हो सकता है। इसके साथ कर्मचारी की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, नियुक्ति से संबंधित अभिलेख, आवश्यक प्रमाण-पत्र तथा वर्तमान में उसके द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन एवं कार्यालयीन कार्यों का परीक्षण भी स्थिति स्पष्ट कर सकता है।

मामला सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं, डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा सवाल- नगर परिषद के शासकीय पोर्टलों पर होने वाली प्रविष्टियां, ऑनलाइन रिकॉर्ड, डिजिटल अभिलेख और कार्यालयीन पत्राचार सीधे प्रशासनिक कामकाज से जुड़े होते हैं। ऐसे में तकनीकी जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारी की दक्षता महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि ऑनलाइन कार्यों में तकनीकी कमी होती है तो उसका प्रभाव नागरिक सेवाओं और पात्र हितग्राहियों से जुड़े कार्यों पर पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि संबंधित कर्मचारी निर्धारित योग्यता रखता है और अपना कार्य नियमानुसार कर रहा है, तो निष्पक्ष जांच उसके खिलाफ उठ रहे सवालों पर भी विराम लगा सकती है।

पात्रता पर सवाल तो जांच से परहेज क्यों?

शिकायत गलत है तो दस्तावेज स्थिति स्पष्ट करेंगे, सही है तो जिम्मेदारी तय करने का रास्ता खुलेगा सवाल यही है कि यदि किसी कर्मचारी की योग्यता को लेकर आपत्तियां उठ रही हैं तो उनका परीक्षण क्यों न कराया जाए? यदि शिकायतें निराधार हैं तो नगर परिषद संबंधित दस्तावेज और निर्धारित पात्रता के आधार पर स्थिति स्पष्ट कर सकती है। पारदर्शिता का तकाजा है कि नियुक्ति से लेकर वर्तमान कार्यप्रणाली तक उपलब्ध सरकारी अभिलेखों की नियमानुसार समीक्षा हो, ताकि न किसी कर्मचारी पर बेवजह सवाल खड़े हों और न ही किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी की आशंका बनी रहे। **कार्यालय प्रमुख से जानना चाहा पक्ष, नहीं मिला जवाब-** मामले में नगर परिषद भुआ-बिछिया के सीएमओ राजेश मार्को का पक्ष जानने के लिए दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। समाचार प्रकाशन तक उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।

अब इन सवालों का जवाब जरूरी

संबंधित कर्मचारी के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता क्या है? नियुक्ति के समय प्रस्तुत तकनीकी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हुआ था या नहीं? कर्मचारी वर्तमान में किन-किन शासकीय पोर्टलों और ऑनलाइन कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहा है? तकनीकी दक्षता को लेकर शिकायत या आपत्ति प्राप्त हुई है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी से कार्यक्षमता का परीक्षण कराया जाएगा? **निष्पक्ष जांच से ही साफ हो सकती है तस्वीर-** फिलहाल उपलब्ध जानकारी संबंधित कर्मचारी की योग्यता या कार्यक्षमता को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करती। इसलिए आरोपों को तथ्य मान लेने के बजाय योग्यता, नियुक्ति अभिलेख और तकनीकी कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच से स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग के स्तर पर अभिलेखों की समीक्षा तथा आवश्यक होने पर तकनीकी परीक्षण कराया जाता है, तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि उठाए जा रहे सवालों का आधार क्या है और संबंधित नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली निर्धारित नियमों के अनुरूप है या नहीं।

अधीक्षक अनिल कुमार उइके निलंबित, 8 नाबालिग छात्रावास से निष्कासित; खबर का हुआ असर, कलेक्टर के निर्देश पर जांच के बाद कार्रवाई

पाठा सिहोरा हॉस्टल में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई

दैनिक रेवांचल टाईम्स - मंडला/ नैनपुर। विकासखंड नैनपुर के पाठा सिहोरा स्थित आदिवासी बालक छात्रावास में बच्चों के बीच हुई मारपीट और हाथ जलाने की घटना के बाद आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई की है। मामले की जांच के बाद छात्रावास अधीक्षक अनिल कुमार उइके को निलंबित कर दिया गया है। वहीं छात्रावास में गठित पालक-शिक्षक संघ समिति के निर्णय के बाद घटना में शामिल बताए जा रहे 8 नाबालिग बच्चों को छात्रावास से निष्कासित किया गया है। बताया गया कि 21 सितंबर को छात्रावास में कुछ बच्चों द्वारा परिसर के अंदर भुट्टा भूने जाने को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान बच्चों के बीच विवाद बढ़ गया और हाथ जलाने की घटना सामने आई। घटना में शामिल सभी बच्चे नाबालिग बताए जा रहे हैं।



रेवांचल टाइम्स
खबर का असर

अधीक्षक की गैरमौजूदगी ने बढ़ाए सवाल- घटना के समय छात्रावास अधीक्षक अनिल कुमार उइके के उच्चाधिकारियों को सूचना दिए बिना बालाघाट चले जाने की बात सामने आई। इसी दौरान अंशकालीन चपरासी के भी छात्रावास में मौजूद नहीं होने की जानकारी सामने आई। वहीं ऐसे में छात्रावास में नाबालिग बच्चे बिना किसी जिम्मेदार वयस्क की निगरानी के रह गए। सवाल उठना स्वाभाविक था कि यदि इस दौरान कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसकी जवाबदेही किसकी होती? प्रशासन ने इसी गंभीर लापरवाही को कार्रवाई का आधार बनाया। कलेक्टर मंडला के निर्देश पर गठित जांच के बाद सहायक आयुक्त अरुण शुक्ला द्वारा अधीक्षक को निलंबित किया गया। वहीं अंशकालीन चपरासी को भी छात्रावास से हटाने की कार्रवाई की गई है।

8 बच्चों को छात्रावास से किया निष्कासित- मामले में छात्रावास में गठित पालक-शिक्षक संघ समिति द्वारा संबंधित बच्चों के पालकों को बुलाकर चर्चा की गई। चूंकि सभी बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने आपसी सहमति से 8 बच्चों को छात्रावास से निष्कासित करने का निर्णय लिया। यहां निष्कासन का अर्थ बच्चों की पढ़ाई बंद करना नहीं है। संबंधित बच्चे विद्यालय में पढ़ाई जारी रखेंगे, लेकिन छात्रावास में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। समिति का उद्देश्य बच्चों को उनकी गलती का अहसास कराना और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकना बताया गया है।

खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन- पाठा सिहोरा छात्रावास की घटना सामने आने के बाद मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था। इसके बाद कलेक्टर मंडला के निर्देश पर जांच समिति गठित की गई। सहायक आयुक्त अरुण शुक्ला ने भी छात्रावास का निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी ली। जांच के बाद अधीक्षक पर निलंबन की कार्रवाई और अंशकालीन चपरासी को हटाने का निर्णय सामने आया है।

नाबालिगों के मामले में कार्रवाई के साथ सुधार भी जरूरी

घटना ने छात्रावासों में नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। छात्रावास में जिम्मेदार कर्मचारी की मौजूदगी, बच्चों की नियमित निगरानी और आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इसकी समीक्षा आवश्यक है। पाठा सिहोरा की घटना में प्रशासनिक कार्रवाई भले ही सामने आ गई हो, लेकिन अब चुनौती यह है कि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और जिम्मेदार कर्मचारियों की अनुपस्थिति को किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जा सकता।



स्वामी,प्रकाशक, मुद्रक, मुकेश श्रीवास द्वारा मां रेवा पब्लिकेशन जबलपुर 68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड मुस्कान प्लाजा के पीछे MR-4 रोड उखरी जबलपुर से मुद्रित एवं सिविल लाईन जवाहर वार्ड मंडला से प्रकाशित। प्रधान संपादक-मुकेश श्रीवास, सिविल लाईन, जवाहर वार्ड मंडला । मो. 9406771592, संपादक - प्रहलाद उइके
RNI. Reg. No MPHIN/2016/69877 (समाचार पत्र के लिये पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार) (न्यायालयीन क्षेत्राधिकार मंडला) Email:- revanchaltimes@gmail.com web-revanchaltimes.in